हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

वार्षिक योजना बजट

2023-24

के लिए

माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु दिनांक 01, 02 तथा 03 फरवरी, 2023 को माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों की कार्यवाही ।

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002

विषय सूची

क. सं. / जिला	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	पृष्ठ
1.	2.	3.
सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, के स्वागत भाषण का संक्षिप्त विवरण ।		1
1. ऊना		
1.	गगरेट	1
2.	ऊना	2
3.	कुटलैहड़	2–3
2. हमीरपुर		
1.	भोरंज	3
2.	सुजानपुर	3–4
3.	हमीरपुर	4
4.	बड़सर	4–5
3. कुल्लू		
1.	मनाली	6
2.	बन्जार	6
3.	आनी	6–7
4. सिरमौर		
1.	पच्छाद	7
2.	नाहन	7–8
3.	श्री रेणुका जी	8–9
4.	पावंटा	9–10
5. काँगड़ा		
1.	नूरपुर	10
2.	इन्दौरा	10
3.	जसवां–प्रागपुर	10–11
4.	फतेहपुर	11
5.	ज्वालामुखी	11–12
6.	जयसिंहपुर	12–13
7.	सुलह	13–14
8.	कांगड़ा	14
9.	शाहपुर	14–15
10.	धर्मशाला	16
6. सोलन		
1.	नालागढ़	16–17
2.	कसौली	17–18

7. बिलासपुर		
1.	झंडूता	18
2.	घुमारवीं	18–19
3.	बिलासपुर	19–20
4.	श्री नैना देवी जी	20–21
8. मण्डी		
1.	करसोग	21
2.	सुन्दरनगर	21–23
3.	नाचन	23
4.	द्रंग	23–24
5.	जोगिन्द्रनगर	24
6.	धर्मपुर	24–25
7.	मण्डी	25–26
8.	बल्ह	26
9.	सरकाघाट	26–27
9. चम्बा		
1.	चुराह	27–28
2.	भरमौर	28
3.	चम्बा	28–29
4.	डलहौजी	29–30
10. शिमला		
1.	चौपाल	30–31
2.	ठियोग	31
3.	शिमला	31–32
4.	रामपुर	32–33
11. लाहौल–स्पिती		
1.	लाहौल–स्पिती	33–34
मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार, का धन्यवाद प्रस्ताव ।		34–35
माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश ।		35–42
माननीय मुख्य मन्त्री का उद्घाटन भाषण (अनुबन्ध ‘क’)		43–44
दो दिवसीय बैठकों की जिलावार समय सारणी।		45
जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार बैठकों में भाग लेने वाले माननीय मन्त्रियों एवं विधायकों का ब्यौरा ।		46–47

वार्षिक योजना 2023-24 की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 01, 02 एवं 03 फरवरी, 2023 को श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खू, माननीय मुख्य मन्त्री, की अध्यक्षता में हुई बैठकों की कार्यवाही ।

....

सर्वप्रथम श्री अक्षय सूद, सचिव (योजना) ने माननीय मुख्य मन्त्री, समस्त माननीय मन्त्रीगण, माननीय मुख्य संसदीय सचिवों, माननीय विधायकों, मुख्य सचिव, समस्त प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों का वार्षिक बजट 2023-24 के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित इस बैठक में स्वागत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय विधायकों के साथ विचार-विमर्श के लिए निर्धारित बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन बैठकों में माननीय विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के अतिरिक्त उनसे अन्य बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त होते हैं। यह सुझाव राज्य के आगामी वार्षिक बजट तैयार करने तथा प्रदेश के सन्तुलित एवं तीव्र विकास के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। सचिव (योजना) ने स्पष्ट किया है कि सम्बन्धित विभाग, विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं की प्रगति की जानकारी समय-समय पर विधायकों को उपलब्ध करवाते हैं तथा उनसे यह अपेक्षा है कि भविष्य में भी योजनाओं की जानकारी समय-समय पर उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। योजना विभाग द्वारा विधायक प्राथमिकताओं की सम्पूर्ण जानकारी फरवरी, 2021 से ऑनलाईन कर दी गई थी। माननीय विधायक इस ऑनलाईन साफ्टवेयर का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं का ब्यौरा जानने एवं अपनी विधायक प्राथमिकताओं का **substitution** भी ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी माननीय विधायकों के नए यूजर आईडी और पासवर्ड हिमाचल प्रदेश विधान सभा की वैबसाईट पर उपलब्ध ई-मेल आईडी पर भेज दिए गए हैं। सभी माननीय विधायक आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी विधायक प्राथमिकताओं को ऑनलाईन भी प्रेषित कर सकते हैं। माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं की योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में समय-समय पर मुख्य सचिव के स्तर पर इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया कि वह अपने स्तर पर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और कार्यों को गति प्रदान करें। यह भी अनुरोध किया गया कि सभी विभाग माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित माननीय विधायक तथा योजना विभाग को भी सूचित करेंगे। तत्पश्चात सचिव(योजना) ने माननीय मुख्य मन्त्री से आग्रह किया कि वे अपने सम्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उदघाटन भाषण **(अनुबन्ध-"क")** के उपरान्त चुनाव क्षेत्रवार बैठक का शुभारम्भ किया । जिला एवं चुनाव क्षेत्रवार तीन दिवसीय बैठकों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र. सं.	**जिला / माननीय विधायक /निर्वाचन क्षेत्र / बैठक में उठाये गए मुद्दे**	**सम्बन्धित विभाग**
1.	2.	3.
1. जिला ऊना		
1. श्री चैतन्य शर्मा, गगरेट		
1.	गगरेट नगर परिषद के साथ लगती सभी पंचायतों की शिकायतों का निपटारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।	शहरी विकास विभाग
2.	गगरेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नगर पंचायत के अन्तर्गत सेना की काफी अधिक भूमि खाली पड़ी है इसे राज्य सरकार के अधीन लाया जाए ताकि वहां पर इन्डोर स्टेडियम या बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कर क्षेत्र की जनता को इसका लाभ प्रदान किया जा सके।	उपायुक्त ऊना/ राजस्व विभाग
3.	स्वां नदी तटीयकरण के अगले चरण को शीघ्र आरम्भ कर इस कार्य को अविलम्ब पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग

2.	**श्री सतपाल सिंह सत्ती, ऊना**	
1.	1 अप्रैल, 2022 के बाद अधिसूचित जिन संस्थानों को बन्द किया गया है उन पर पुनः विचार कर जनता के हित में दोबारा से अधिसूचित किया जाए।	सामान्य प्रशासन
2.	मुफ्त में दी जा रही योजनाओं जैसे बिजली, राशन, धनराशि इत्यादि को बन्द किया जाए (जरूरतमंदों को छोड़कर) ताकि आर्थिक तंगी से बचा जा सके और प्रदेश सरकार को निरन्तर राजस्व आता रहे जिससे हिमाचल प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके तथा आर्थिक रूप से हिमाचल मजबूत बन सके।	समस्त विभाग
3.	प्रदेश के गरीब परिवारों को जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें मकान हेतु 2–3 बिस्वा भूमि प्रदान की जाए ताकि उन्हें भी मकान की सुविधा प्राप्त हो सके तथा जिनके पास अपनी भूमि है और सरकारी भूमि पर कब्जा किए बैठें हैं उनसे भूमि वापिस ली जाए।	समस्त उपायुक्त / समस्त विभाग
4.	सीमा से सटे निर्वाचन क्षेत्रों में नशे पर पूर्ण रोक लगाई जाए ताकि प्रदेश के युवाओं / जनता को इससे बचाया जा सके।	पुलिस विभाग
5.	सभी विभागों में योजनाओं की टैण्डर प्रक्रिया को कम किया जाए।	समस्त विभाग
6.	भवन निर्माण के समय बिजली, पानी, प्लास्टर, रंग इत्यादि के कार्य सुचारू रूप में (step by step) किए जाएं इससे निर्माण में तेजी आएगी तथा योजना की लागत में भी वृद्धि नहीं होगी, इसके लिए लोक निर्माण विभाग की Architect wing and Electrical Wing को मर्ज कर दिया जाए।	लोक निर्माण / हिमुडा/ पंचायती राज/ ग्रामीण विकास / समस्त विभाग
7.	हमीरपुर में लोक निर्माण विभाग की Architect wing खोली जाए। Architect के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए और नए पद सृजित कर इस विभाग को सुदृढ़ किया जाए जिससे नक्शे इत्यादि का कार्य शीघ्र होगा तथा निर्माण कार्यों में तीव्रता आएगी।	लोक निर्माण विभाग
8.	मातृ एंव शिशु अस्पताल ऊना में फायर फाईटिंग सिस्टम को शीघ्र स्थापित कर कार्य निर्धारित समय में पूरा करें ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके।	स्वास्थ्य/लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त ऊना
9.	आयुर्वेदा अस्पताल जोल में तीन डॉ0 हैं वहां ओ.पी.डी. न के बराबर है वहां से कुछ डॉक्टरों को जिला आर्युेदिक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाए।	आयुर्वेदा विभाग
10	ऊना सचिवालय भवन के द्वितीय चरण का कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त ऊना
11	पुराना बस अडडा के स्थान पर नया बस अडडा बना पड़ा है जिसमें अंडर ग्राउंड पार्किंग, शॉपिंग कॉम्पलैक्स, मॉल इत्यादि को पी.पी.पी. मोड पर प्रदान किया जाए जिससे सरकार को भी आय होगी।	बस अडडा प्राधिकरण
12	ऊना शहर के लिए बाईपास का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	**श्री दविन्द्र कुमार भुटटो, कुटलैहड़**	
1.	डीएसपी कार्यालय के लिए बंगाणा में भवन उपलब्ध है अतः इसे ऊना के स्थान पर बंगाणा किया जाए।	पुलिस विभाग
2.	सब जज कोर्ट ऊना, बंगाणा के नाम से चल रहा है, बंगाणा से ही इसका संचालन किया जाए जिसके लिए मिनी सचिवालय के भवन में पर्याप्त कमरें भी उपलब्ध हैं।	उपायुक्त ऊना
3.	निर्वाचन क्षेत्र के लिए खेल मैदान का निर्माण किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग

4.	जल शक्ति विभाग में विधायक प्राथमिकता तथा अन्य सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	बंगाणा क्षेत्र में विभागों को जरूरत से अधिक भूमि स्थानांतरित की गई है। उपभोग के बाद बची शेष भूमि को सरकार को वापिस किया जाए ताकि इस भूमि का अन्य कार्यालय बनाने के लिए उपयोग किया जा सके।	राजस्व विभाग
6.	लोक निर्माण विभाग में सड़कों के निर्माण में पीसी तथा बीसी में से केवल बीसी का ही उपयोग होना चाहिए।	लोक निर्माण विभाग
2.	**जिला हमीरपुर**	
1.	**श्री सुरेश कुमार, भोरंज**	
1.	सब डिवीजन भोरंज में स्कूल तथा आवासीय परिसर की कमी को दूर किया जाए।	शिक्षा / सम्बन्धित विभाग
2.	बस अडडा भोरंज के लिए अस्पताल के साथ जो भूमि परिवहन विभाग को दी है उसे बदलकर अन्य स्थान पर किया जाए ताकि आधुनिक रूप में बस अडडे का निर्माण हो सके और अस्पताल का सौन्दर्यकरण भी हो सके।	बस अडडा प्राधिकरण / स्वास्थ्य विभाग/ उपायुक्त ऊना
3.	भोरंज अस्पताल का कार्य धीमी गति से चल रहा है विद्युत विभाग के टैण्डर की प्रक्रिया को पूर्ण कर इसे तीव्रगति के साथ शीघ्र पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य/लो०नि० विभाग/ HPSEBLtd.
4.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
5.	भोरंज क्षेत्र के लिए 24 घंटे पीने के पानी की योजना जिसमें दो नलों की सुविधा एक पीने के पानी तथा दूसरा अन्य कार्यों के उपयोग हेतु मॉडल स्कीम के रूप में निर्मित की जाए	जल शक्ति विभाग
6.	हमीरपुर, मण्डी तथा बिलासपुर के क्षेत्रों को व्यास नदी से पानी पर्याप्त मात्रा में नही मिल पा रहा है इसलिए सतलुज नदी से पानी उठाने के लिए एक बड़ी योजना का निर्माण कर इन क्षेत्रों में पानी की समस्या का निदान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
2.	**श्री राजिन्द्र राणा, सुजानपुर**	
1.	लोक निर्माण की अधिसूचना कि 1 लाख से 5 लाख तक के टैण्डर नहीं होंगे को निरस्त किया जाए तथा MLA, DCP Head या अन्य किसी माध्यम से लोक निर्माण विभाग को जो पैसे दिए गए हैं उनका टैण्डर ऑनलाईन न लगाकर पुरानी पद्धति से लगाया जाए ताकि रुके कार्यों को पूरा किया जा सके।	लोक निर्माण/ ग्रामीण विकास विभाग/ उपायुक्त
2.	नाबार्ड में स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी 06 सड़कों की डी.पी.आरज. को शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	टाऊन हाल सुजानपुर का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लो०नि०/ शहरी विकास विभाग/ उपायुक्त हमीरपुर
4.	सुजानपुर अस्पताल को 50 बिस्तर से 100 बिस्तर किया जाए और विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	बमसन क्षेत्र में Govt. Degree College खोला जाए।	शिक्षा विभाग
6.	बस अडडा सुजानपुर के बाहर पालमपुर चौक के नामक स्थान के साथ प्राथमिक विद्यालय को हटाकर वहां बस अडडा बनाया जाए तथा टाउन हॉल के साथ भूमि पर इस विद्यालय का निर्माण किया जाए।	प्रारम्भिक शिक्षा/ बस अडडा प्राधिकरण/ उपायुक्त
7.	जल शक्ति विभाग तथा विद्युत विभाग के डिवीजन खोलने की जिस अधिसूचना को निरस्त किया गया है उसे फिर से बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ सामान्य प्रशासन/ HPSEBLtd.

8.	लोक निर्माण विभाग में ठेकेदार कम मूल्य पर ठेका ले लेते हैं और समय पर काम नहीं कर पाते हैं ऐसे ठेकेदारों को 3–5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9.	विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डी.पी.आर. को समय में (Time bound) तैयार किया जाए।	लोक निर्माण/जल शक्ति विभाग
10	नाबार्ड के तहत विधायक प्राथमिकता की योजनाओं में सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई के स्थान पर अन्य विकास की योजनाओं को शामिल करने बारे अधिसूचना जारी की जाए। इसके लिए 15 करोड़ का बजट प्रति निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाए जिससे सभी निर्वाचन क्षेत्रों का एक समान विकास सम्भव होगा।	योजना विभाग
3. श्री आशीष ठाकुर, हमीरपुर		
1.	पक्का बरोह के पास प्रस्तावित नया बस अड्डा तथा पुराना बस अड्डा हमीरपुर का निर्माण कार्य नवीनतम तकनीक तथा आधुनिक सुविधाओं के साथ शीघ्र आरम्भ करने के लिए पी.पी.पी. मोड पर क्लब कर टैण्डर लगाया जाए जिससे ठेकेदार रुचि लेगा और कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जा सकेगा। साथ ही इन बस अड्डों में शॉपिंग मॉल, पार्किंग की भी व्यवस्था प्रदान की जाए।	बस अड्डा प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग
2.	लगभग 2800 कनाल की भूमि पशुपालन विभाग के पास लीज के रूप में उपलब्ध है इस भूमि पर Vetrinary Institute/ College का निर्माण किया जाए जिससे पूरे जिला हमीरपुर को इसका लाभ मिलेगा।	पशु पालन विभाग/ उपायुक्त
3.	झगड़्याणी विद्यालय में साईंस लैब का निर्माण किया जाए।	शिक्षा विभाग
4.	अणु पंचायत को सीवरेज की सुविधा से जोड़ा जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	उपायुक्त कार्यालय से ऊपर की तरफ उपलब्ध भूमि पर शहीद स्मारक निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	सैनिक कल्याण विभाग/ उपायुक्त
6.	वन विभाग के अधीन हीरानगर नामक स्थान पर चिल्ड्रन पार्क है इसके सौन्दर्यकरण/विकास/सुदृढ़िकरण के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	वन विभाग
7.	जल शक्ति विभाग के डिवीजन में कुछ पंचायतें बड़सर तथा भोरंज डिवीजन में पड़ती हैं इन्हें हमीरपुर में शामिल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	सब डिवीजन टिक्कर को निरस्त करने की अधिसूचना पर पुनः विचार कर इसे जनहित में खोला जाए।	जल शक्ति/ सामान्य प्रशासन विभाग
9.	हमीरपुर शहर में सड़कों का निर्माण लगभग पूर्ण है इसलिए इस पूरे शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थीयों की सुरक्षा के मध्यनजर पूरे क्षेत्र को सी.सी.टी.वी. से कवर किया जाए और इसका पूरा संचालन पुलिस विभाग के Commandant Control Room से किया जाए।	पुलिस विभाग
4. श्री ईन्द्र दत्त लखनपाल, बड़सर		
1.	बस अड्डा मैहरे/बड़सर के निर्माण सम्बन्धी भूमि व अन्य सभी विवादों का निपटारा कर कार्य को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए या ट्रस्ट की 150 कनाल भूमि या फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की भूमि पर इस बस अड्डे का निर्माण करने बारे विचार किया जाए।	बस अड्डा प्राधिकरण/ राजस्व विभाग / उपायुक्त हमीरपुर
2.	भोटा बस अड्डे के लिए भूमि तथा बजट उपलब्ध है शीघ्र इसका कार्य आरम्भ किया जाए।	बस अड्डा प्राधिकरण
3.	भवनों के निर्माण के समय मुरम्मत एवं रख–रखाव के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग

4.	महाविद्यालय बड़सर के साथ–साथ प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में सफाई व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए नए पद सृजित कर भरे जाएं।	शिक्षा विभाग
5.	शिक्षण संस्थान रैली जजरी के स्कूल के जर्जर भवन के साथ–साथ क्षेत्र में विद्यमान अन्य सरकारी कार्यालयों के जर्जर भवनों को गिराकर नए भवनों का निर्माण किया जाए।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा/ समस्त सम्बन्धित विभाग
6.	शिक्षण संस्थानों में बैठने के लिए बैंच नहीं है, चटाई/टाट नहीं है, शौचालय नहीं है/ठीक नहीं हैं की व्यवस्था को सुधारा जाए।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
7.	निर्वाचन क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की पुरानी पम्पिंग मशीनरी को बदला जाए साथ ही डी.पी.आर. बनाते समय मुरम्मत एवं रख–रखाव शीर्ष को अनिवार्य किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	अस्थाई पुलिस चौकी बिझड़ी, भोटा तथा ढटवाल को अपग्रेड/स्थायी किया जाए।	पुलिस विभाग
9.	पीएचसी भोटा को अपग्रेड किया जाए तथा इसमें स्टाफ नर्स व एमडी स्पैस्लिस्ट प्रदान किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
10	क्षेत्र की तीन आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरीज में फार्मासिस्ट तथा डॉक्टरों के पद स्वीकृत कर इन्हें चालू किया जाए।	आयुर्वेदा विभाग
11	बड़सर तथा बिझड़ी में टाउन हॉल का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास विभाग
12	बिझड़ी का ब्लॉक भवन क्षमतानुसार छोटा है इसे अपग्रेड किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
13	सी.एच. बड़सर में रेडियोलॉजिस्ट के पद को स्थायी तौर पर भरा जाए। साथ ही बड़सर अस्पताल, सीएचसी बिझड़ी तथा पीएचसी भोटा में एमडी स्पैस्लिस्ट तीनों जगह पर स्थायी रूप से नियुक्त करें।	स्वास्थ्य विभाग
14	ईएनटी के अधीन स्पीच तथा आडियोलॉजिस्ट के पदों को भी अविलम्ब भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
15	बिझड़ी तथा मैहरे बाईपास का निर्माण शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
16	क्षेत्र में विद्यमान कस्बों में सीवरेज की सुविधा प्रदान की जाए तथा बड़सर में नगर पंचायत का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास/ जल शक्ति विभाग
17	बिझड़ी तथा भोटा में पार्किंग का निर्माण किया जाए।	ग्रामीण विकास/ शहरी विकास वि0
18	मिनी सचिवालय मैहरे के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए रू0 4–5 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाए।	राजस्व/ लो0नि0 विभाग
19	दयोटसिद्ध मन्दिर को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए माता नैनादवी जी से बछरेटू मन्दिर और फिर टयालू–क्यालू मन्दिर, मूल स्थान बाबा शहतलाई तथा दयोटसिद्ध मन्दिर को धार्मिक सर्किट के रूप में आपस में जोड़ने के लिए रोपवे का भी निर्माण किया जाए।	पर्यटन विभाग / RTDC (Ropeways)
20	विधायक निधि तथा ऐच्छिक निधि की अन्तिम रूकी किश्त को जारी किया जाए।	योजना/ग्रामीण विकास विभाग
21	मुख्यमंत्री सहारा योजना के अन्तर्गत मरीजों को समय पर पूरा पैसा प्रदान किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
22	श्रम कल्याण बोर्ड में रूके हुए Justified Claims तुरन्त Settle किए जाएं।	Labour welfare Board
23	कैन्सर तथा किडनी के मरीज ईलाज के लिए गरीब व्यक्ति शिमला या अन्य स्थान पर जाते हैं वहां इनके रूकने की पूर्ण व्यवस्था की जाए।	स्वास्थ्य विभाग

3.	जिला कुल्लू	
	1. श्री भुवनेश्वर गौड़, मनाली	
1.	पर्यटन स्थान रोहतांग पास के क्षेत्र में एनजीटी के आदेशों का काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है इन पर विचार किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिलेगा/बढ़ेगा साथ ही सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।	पर्यटन विभाग/ उपायुक्त
2.	टोल प्लाजा डोलूनाल द्वारा गाड़ियों के आने-जाने पर लिए जाने वाले कर में पिछले दो माह में लगभग 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है इसे कम किया जाए। साथ ही अगर गाड़ी पर फास्ट टैग नहीं है तो दोगुना कर आने-जाने का अलग-अलग लिया जाता है इस पर भी विचार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त
3.	मनाली में 50 बिस्तर अस्पताल घोषित किया है हालात वैसे ही हैं और आक्सीजन प्लांट भी स्थापित नहीं किया गया है जो अभी पिछले दो साल से पर्वतारोहण खेल संस्थान के पास सड़ रहा है इस पर भी गम्भीर विचार किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ खेल पर्वतारोहण संस्थान
4.	व्यास नदी का कोटी से औट का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	व्यास नदी में आई बाढ़ के कारण भूमिहीन लोगों तथा जिन लोगों की भूमि बही है उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त कुल्लू
6.	मनाली में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए 3-4 हजार गाड़ियों की क्षमता वाली पार्किंग का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास विभाग
	2. श्री सुरेन्द्र शौरी, बन्जार	
1.	विधायक प्राथमिकता योजना में सड़कों की डी.पी.आर. बनाने में वन विभाग की आपत्तियों (FCA/FRA) का स्थायी तथा तीव्र समाधान निकाला जाए ताकि सड़कों का निर्माण शीघ्र हो सके।	लोक निर्माण / वन विभाग
2.	सैंज घाटी में स्थापित प्रोजेक्टों (NHPC stage-II & III) से विस्थापित / प्रभावित कुल 98 लोगों में से शेष 65 का वन टाईम सैटलमेंन्ट की जाए तथा उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाए।	HPPCLtd./राजस्व विभाग (R&R) / उपायुक्त कुल्लू
3.	पशु अस्पताल बजौरा को निरस्त कर दिया गया इसे पुनः चालू किया जाए।	पशु पालन विभाग
4.	अनछूहे पर्यटन स्थलों जैसे तीर्थन वैली, जिभी-शोझा, जलोड़ी के साथ गाड़ा गुशैणी, दयार, गड़सा का क्षेत्र है वहां पर बाहर के लोगों द्वारा 6-7 मंजिलें भवनों का निर्माण किया जा रहा है इसे रोका जाए तथा निर्वाचन क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश में केवल 5-6 कमरों के निर्माण (Eco friendly) की ही अनुमति मिले ताकि पर्यावरण सुरक्षित व सुन्दर बना रहे।	पर्यटन / पंचायती राज विभाग
5.	एन.एच. 305 औट-लुहरी के कार्य तथा जलोड़ी सुरंग निर्माण के कार्य को तीव्रता तथा गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।	लो0नि0 विभाग
6.	पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में ट्रैफिक विंग खोली जाए।	पुलिस विभाग
	3. श्री लोकेन्द्र कुमार, आनी	
1.	निर्वाचन क्षेत्र आनी में निरस्त किए गए संस्थानों को पुनः खोला जाए जिसमें निरमण्ड ब्लॉक के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय पजैण्डा को प्राथमिकता प्रदान की जाए।	पशु पालन / समस्त सम्बन्धित विभाग
2.	पर्यटन की दृष्टि से आनी क्षेत्र को भी विकसित किया जाए साथ ही जलोड़ी पास में पर्यटक रोपवे का निर्माण भी किया जाए।	पर्यटन विभाग/ RTDC
3.	बगासराहन से बठाड़ के लिए सुरंग तथा जलोड़ी पास-रघुपुर गढ़ सड़क का निर्माण किया जाए। साथ ही पर्यटन की दृष्टि से जलोड़ी जोत कैंची से रोहाचड़ा सड़क का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण वि0

4.	क्षेत्र में विद्यमान शैक्षणिक तथा तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की दयनीय स्थिति में सुधार किया जाए। अध्यापकों की स्थायी नियुक्तियां की जाए तथा पुराने जर्जर भवनों या किराए के भवनों के स्थान पर अपने भवन प्रदान किए जाएं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से आ रहे अध्यापकों के लिए आवास का भी प्रबन्ध किया जाए।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा विभाग
5.	बागासराहन क्षेत्र को पूर्व में नई राहें नई मंजिलें में शामिल किया गया है इसके कार्य को तीव्रगति से पूरा किया जाए।	पर्यटन विभाग
6.	आनी अस्पताल में रिडियोग्राफर की स्थायी व्यवस्था की जाए।	
7.	सर्दियों में हमारा क्षेत्र लगभग 3-4 महीने के लिए जिला मुख्यालय से कट हो जाता है इसलिए उन दिनों में बसों की आवाजाही आनी से ही चलने दी जाए ताकि लोगों को खनाग तक ही सही बस सेवा उपलब्ध होती रहे। साथ ही खनाग-शिमला बस सेवा और कुल्लू से आनी वाया कोठी बस सेवा आरम्भ की जाए।	परिवहन विभाग
8.	दूध में डिग्री तथा फैट के नाम पर विभाग के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। मिल्क फैडरेशन तथा पशु पालन विभाग इस पर गौर करे।	पशु पालन विभाग/ HP Milk Fedration
9.	राणाबाग से कण्डीबाग, बालू तक सड़क को शीघ्र पक्का किया जाए। साथ ही बुर्जीखडड सड़क पर भी विभाग गौर करे। इस सड़क से बहुत सी पंचायतों की दूरी कुल्लू से कम हो जाएगी।	लोक निर्माण विभाग
10	चौराधार से पनेउ सड़क की डी.पी.आर. को शीघ्र तैयार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
11	जलोड़ी पास के लिए घयागी से उठाऊ जल योजना का निर्माण किया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।	जल शक्ति/ पर्यटन विभाग
12	आनी-दिल्ली हि0प्र0 परिवहन सेवा आरम्भ की जाए।	परिवहन विभाग
4. जिला सिरमौर		
1. श्रीमति रीना कश्यप, पच्छाद		
1.	3-4 विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली ओच्छघाट-नेरीपुल-छैला सड़क की दयनीय स्थिति को ठीक किया जाए तथा इसे डबल लेन बनाया जाए।	लोक निर्माण वि0
2.	सराहां अस्पताल को 100 बिस्तर किये जाने अधिसूचना को निरस्त किया गया है इसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	राजगढ़ अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद को भरा जाए या सप्ताह में 3-4 दिन के लिए डेपयूटेशन पर ही भेजकर काम चलाया जाए और सराहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन उपलब्ध करवाई जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	जल शक्ति विभाग के डिवीजन राजगढ़ तथा विद्युत विभाग के डिवीजन सराहां में खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है उसे बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ सामान्य प्रशासन/ HPSEBLtd.
5.	पर्यटन की दृष्टि से हब्बन वैली से चूरधार में रोपवे का निर्माण किया जाए।	पर्यटन/RTDC
6.	शिरगुल महोदव की जन्म स्थली शाया मन्दिर को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए तथा इस मन्दिर का भव्य निर्माण किया जाए।	पर्यटन/ भाषा कला एवं संस्कृति विभाग
2. श्री अजय सोलंकी, नाहन		
1.	मेडिकल कॉलेज नाहन के लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा कार्डियोलॉजिस्ट के पद को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
2.	मेडिकल कॉलेज के लिए मेन सड़क से वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया जाए।	स्वास्थ्य/लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त

3.	मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट के पद को भरा जाए, सीटी स्कैन तथा अल्ट्रासाउंड की स्थिति को ठीक किया जाए। इसके साथ ही मैटरनिटी वार्ड की दयनीय स्थिति को ठीक करने के लिए गाईनी विभाग में पूर्ण/अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	राजाओं के समय से सेना क्षेत्र में रह रहे लोगों को मकान मुरम्मत की भी अनुमति सेना से लेनी पड़ती है लोगों के रास्ते बन्द पड़े हैं इनकी समस्या का हल किया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त सिरमौर
5.	नाहन निर्वाचन क्षेत्र में टी.सी.पी. के अधीन आई पंचायतों के लोगों को पुराने मकानों के लिए भी घरेलू बिजली, पानी कुनैक्शन इत्यादि लेने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है इनकी समस्या को हल किया जाए।	शहरी विकास विभाग
6.	नाहन शहर में पार्किंग का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास विभाग
7.	मोटरेबल सड़कों की स्थिति का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	क्षेत्र के भूमिहीन लोगों को 2-3 बिस्वां भूमि शीघ्र प्रदान की जाए।	राजस्व विभाग
9.	जल शक्ति विभाग में सिंचाई की सुविधा की पात्रता दो से ढाई लाख प्रति हैक्टेयर की सीमा में वृद्धि की जाए।	जल शक्ति विभाग
10	सीमा क्षेत्र में नशे तथा खनन माफिया पर पूर्ण रोक लगाई जाए।	उद्योग/ पुलिस विभाग
11	सुकेती फासिल पार्क को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	पर्यटन विभाग
12	पेयजल की योजनाओं में फिल्टर नहीं हैं भविष्य में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए।	जल शक्ति विभाग
13	नाहन शहर में सीवरेज की व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए तथा नाहन शहर से निकलने वाले नालों के लिए शहर के बाहर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास/ जल शक्ति विभाग
14	निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों से रह रहे गुज्जरों को कच्चे मकान पर टीन की छत लगाने की अनुमति प्रदान की जाए।	शहरी विकास/ पंचायती राज/ ग्रामीण विकास विभाग / उपायुक्त सिरमौर
3. श्री विनय कुमार, श्री रेणुका जी		
1.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
2.	रेणुका जी को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
3.	रेणुका झील में बढ़ रही सिल्ट बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	रेणुका विकास प्राधिकरण बोर्ड/ उपायुक्त
4.	हरिपुरधार, नौहराधार तथा चूड़धार के लिए चार पड़ाव हैं तीन पड़ाव तक रोपवे का निर्माण किया जाए।	पर्यटन विभाग/ RTDC
5.	चूड़धार के चारों तरफ लगभग 100 कि0मी0 का ट्रैक है। इस ट्रैक की मुरम्मत कर बैटरी कार चलाई जाए।	वन/ लोक निर्माण/ पर्यटन विभाग
6.	Wild Life Sanctuary रेणुका जी में Tiger pair उपलब्ध करवाने के मामले में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। इसी वर्ष इस कार्य को पूरा किया जाए।	वन्य प्राणी विभाग
7.	रेणुका डैम प्रोजेक्ट के कार्य को शीघ्र चालू किया जाए। साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि विस्थापित लोगों को तीव्रगति से अन्य स्थानों पर बिना समस्या के बसाया जाए तथा लोगों को सही मुआवजा Time bond प्रदान किया जाए।	HPPCLtd.

8.	सीवरेज सिस्टम रेणुका का सुधार किया जाए।	जल शक्ति/ शहरी विकास विभाग
9.	सी.आर.एफ. के तहत गिरी नदी पर बनने वाले डबल लेन पुल के निर्माण में लगने वाली वन आपत्तियों का निपटान कर शीघ्र कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10	Govt. Degree College ददाहू में भवन निर्माण और बस अडडे के निर्माण के लिए वन विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों को FCA clearance शीघ्र प्रदान कर भूमि स्थानांतरित की जाए।	वन / शिक्षा/उद्यान परिवहन विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान शैक्षणिक, स्वास्थ्य, विद्युत तथा अन्य सभी विभागों के नए संस्थान/कार्यालय खोलने, अपग्रेड करने के स्थान पर इन सभी संस्थानों/कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग
12	विद्युत विभाग में फिल्ड स्टाफ के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	HPSEBLtd.
13	निर्वाचन क्षेत्र के सब डिवीजनों पौंटा, नाहन, संगड़ाह आदि को re-organize किया जाए तथा सभी विभागों के कार्यालयों की सुविधा एक छत के नीचे प्रदान किए जाएं।	राजस्व/ग्रामीण विकास/ सम्बन्धित विभाग/ उपायुक्त
14	हैण्डपम्प लगाने की बन्द की गई योजना को पुनः चालू किया जाए।	जल शक्ति विभाग
15	प्रदेश में ओबीसी जाति के लोगों को मकान बनाने के लिए मिलने वाली संख्या में बढ़ोतरी की जाए तथा सभी पात्र लोगों को आवास योजना में मिलने वाली धनराशि को भी 1.5 लाख से बढ़ाया जाए।	SOMA Deptt./ सम्बन्धित विभाग
16	रेणुका डैम प्रोजेक्ट के बनने से मुख्य सड़क संगड़ाह को बन्द कर किसी अन्य स्थान से बनाया जाना है जिससे 14 कि0मी0 की दूरी बढ़ रही है। इसके स्थान पर यहां पर एक सुरंग का निर्माण किया जाए।	HPPCLtd. / लोक निर्माण विभाग
4. श्री सुखराम चौधरी, पौंटा		
1.	B&R Sub Division पुरुवाला, दो पशु औषधालय, पटवार सर्कल खोलने तथा सब तहसीलें अपग्रेड करने, की जो अधिसूचनाएं रदद की गई है उसे पुनः बहाल किया जाए।	लोक निर्माण/पशु पालन/राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	हिमाचल तथा उतराखण्ड को जोड़ने वाले पुल का निर्माण उतराखण्ड सरकार द्वारा किया जा रहा है इसकी पूरी कनेक्टीविटी के लिए हिमाचल प्रदेश की ओर से केवल 1 कि0मी0 की सड़क का निर्माण किया जाना है जिसके लिए विभाग शीघ्र भूमि अधिग्रहण कर कार्य सड़क निर्मित करे।	लोक निर्माण विभाग
3.	गिरी नदी से निकलने वाली दो नहरों की दयनीय/ जर्जर स्थिति को सुधारा/मुरम्मत शीघ्र की जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को सिंचाई की सुविधा निरन्तर मिलती रहे ।	जल शक्ति विभाग
4.	जिला सिरमौर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए प्रस्तावित 220 के.वी., 132 के.वी. सीसीए राजबन, 132 के. वी. चारण्डा के सब–स्टेशनों की स्वीकृति प्रदान कर शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए साथ ही 220 के.वी. खोदरी माजरी लाईन के लूप–ईन लूप–आउट कार्य को भी शीघ्र पूरा किया जाए ताकि स्थानीय जनता तथा उद्योगों के लिए निरन्तर सुचारू विद्युत आपूर्ति हो सके।	HPTCLtd.
5.	कालाअम्ब 440 के.वी. सब–स्टेशन बनकर तैयार है। लाईनों की वन आपत्तियों का निपटारा शीघ्र विद्युत आपूर्ति की जाए।	वन विभाग/ HPTCLtd.
6.	नगर परिषद पौंटा को नगर निगम बनाया जाए।	शहरी विकास वि0

7.	पौंटा में पार्किंग का निर्माण किया जाए जिसके लिए भूमि भी उपलब्ध है।	लोक निर्माण/ शहरी विकास वि0
	5. जिला कांगड़ा	
	1. श्री रणधीर सिंह निक्का, नूरपुर	
1.	प्रदेश में बढ़ते नशे (चिट्टा) पर पूर्ण रोक लगाई जाए।	पुलिस विभाग
2.	पंजाब राज्य के साथ लगते क्षेत्रों में अवैध खनन को रोका जाए।	उद्योग / पुलिस विभाग
3.	नूरपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए जिससे साथ लगते 5 निर्वाचन क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ प्राप्त होगा।	स्वास्थ्य विभाग
4.	डयोली से काथल सड़क का निर्माण तथा इन्दौरा के साथ लगते रिट से करसान सड़क में छौंछ खडड पर पुल का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	हरिजन बस्ती के लिए कोलाण से कोहला सड़क का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	नेरा से मकोड़जमन सड़क निर्माण तथा जसूर बाजार से नूरपुर कमेटी को जोड़ने के लिए जब्बर खडड पर पुल का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	ग्राम पंचायत कण्डवाल तथा ब्रांडा के बीच में पेयजल की योजना का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	जटोली ठेड़ा खास तथा गॉंव सुलयाली व साथ लगते क्षेत्र के लिए पेयजल योजना का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
	2. श्री मलेन्द्र राजन, ईन्दौरा	
1.	पंजाब राज्य के साथ लगते क्षेत्रों में अवैध खनन को शीघ्र रोका जाए।	उद्योग/ पुलिस विभाग
2.	प्रदेश में बढ़ते नशे (चिट्टा) पर पूर्ण रोक लगाई जाए।	पुलिस विभाग
3.	पूर्व समय में क्षेत्र की दो सीएचसी को सीएच किया गया है इनमें पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएं। पूरे भवन, ऑपरेशन थियेटर, 2-3 विशेषज्ञ डाक्टर, पूरा तकनीकी स्टाफ इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	चक्की खडड पर पुल सहित डमटाल से माजरा सड़क निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	ठाकुरद्वारा से पराल सड़क पर व्यास नदी की सहायक नदी पर पुल का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6.	तयोड़ा से तयोड़ापतन सड़क पर पानी की मिनरल फैक्ट्री के पास तयोड़ापतन पुल का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	सिंचाई सुविधा के लिए क्षेत्र में 10 टयूबवैलों का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	पेयजल की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 15 नलकूपों का सुधार एवं विस्तार किया जाए।	जल शक्ति विभाग
9.	शाहनहर के शेष कार्य को पूर्ण कर क्षेत्र की जनता को इसकी सुविधा प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
10	निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न उठाऊ पेयजल योजनाओं का सुधार एवं सुदृढ़िकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
	3. श्री बिक्रम सिंह, जसवां-प्रागपुर	
1.	एफसीए तथा एफआरए के तहत रुकी सड़कों की आपत्तियों का निपटारा कर शीघ्र इनकी डीपीआर तैयार कर स्वीकृत किया जाए।	लोक निर्माण/वन विभाग
2.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग

3.	निर्वाचन क्षेत्र में रदद किए गये एसडीएम कार्यालय तथा बीडीओ कार्यालय को पुनः बहाल किया जाए।	राजस्व /ग्रामीण विकास विभाग/ सामान्य प्रशासन
4. श्री भवानी सिंह पठानिया, फतेहपुर		
1.	पुलिस जिला नूरपुर बनाया गया है इसका सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसमें अतिरिक्त गाड़ियां तथा स्टाफ की तैनाती की जाए।	पुलिस विभाग
2.	रैण पुलिस चौकी को थाना बनाया जाए।	पुलिस विभाग
3.	नशे पर पूर्ण रोक लगाने के लिए चिट्टा तस्करों को उनके आय स्त्रोतों से पहचान कर उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।	पुलिस विभाग
4.	मण्ड क्षेत्र में अवैध खनन पर पूर्ण रोक लगाई जाए। जिसके लिए कार्रवाई न करने वाले खनन विभाग को भंग किया जाए।	उद्योग विभाग
5.	बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए पौंग डैम के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन/ श्रम एवं रोजगार विभाग
6.	रोजगार की दृष्टि से अम्ब से लेकर पंजाब सीमा तक औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाए।	उद्योग/ श्रम एवं रोजगार विभाग
7.	पौंग डैम के कैचमेंट एरिया को एक नीति बनाकर कानूनी लड़ाई से वापिस लिया जाए जिससे यहां पर कृषि, बागवानी, पर्यटन इत्यादि को विकसित कर राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए।	राजस्व विभाग
8.	कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्र के पास लम्बित डीपीआरज़ को शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
9.	शाहनहर प्रोजेक्ट के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए केन्द्र से पीएमकेएसवाई या राज्य शीर्ष से रू0 15-16 करोड़ का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10	प्रमुख अभियन्ता, प्रोजेक्ट का कार्यालय फतेहपुर से मण्डी ले जाया गया है इसे वापिस फतेहपुर लाया जाए।	जल शक्ति विभाग
11	सीएचसी रे में पूरे डाक्टर तैनात किए जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
12	राजा का तालाब में मेडिकल कॉलेज खोला जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5. श्री संजय रतन, ज्वालामुखी		
1.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
2.	पुरानी चल रही योजनाओं को पूर्ण करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ लोक निर्माण वि0
3.	निर्वाचन क्षेत्र ज्वालामुखी में लोक निर्माण तथा जल शक्ति विभागों के डिवीजन खोले जाएं।	जल शक्ति / लोक निर्माण विभाग
4.	मध्यम सिंचाई योजना की डी.पी.आर. को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य आरम्भ किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके और वे ज्यादा से ज्यादा कृषि के क्षेत्र का विकास कर सकें।	जल शक्ति विभाग
5.	ज्वालामुखी के अन्तर्गत बीडीओ कार्यालय सुराणी में 51 पंचायतों के लिए खोला जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
6.	क्षेत्र के लिए 5 मुद्रिका बसें प्रदान की जाएं।	परिवहन विभाग
7.	खुंडियां, मझीण तथा लगडू में बस स्टैण्ड का निर्माण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
8.	राजकीय महाविद्यालय खुंडियां तथा मझीण में प्रवक्ताओं के सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	शिक्षा विभाग
9.	लगडू नामक स्थान पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाए।	शिक्षा विभाग
10	टिहरी में पॉलटेक्निक कॉलेज खोला जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
11	सीएच खुंडियां तथा सीएचसी मझीण में सभी श्रेणी के सभी पदों को पूर्ण रूप से भरकर पूरी सुविधाएं प्रदान की जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
12	पिछड़ी पंचायत पीढ़ी में पीएचसी खोली जाए।	स्वास्थ्य विभाग

13	3 स्वीकृत सब–स्टेशनों ठेडा, मझीण तथा देहरियां का निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPTCLtd.
14	निर्वाचन क्षेत्र में व्यास नदी के ऊपर अमतर, सुदौढ़ापतन तथा डिब के पास 3 पुलों का निर्माण किया जाए तथा नखेड़ खडड के ऊपर जन्दराह में धीमी गति से बन रहे पुल को तीव्रगति से शीघ्रातिशीघ्र तैयार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
15	ज्वालामुखी में आने वाले श्रद्धालुओं तथा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एडीबी के माध्यम से ज्वालामुखी का सौन्दर्यकरण किया जाए तथा यात्रियों को ज्वालामुखी शहर में रोकने के लिए पार्किंग, बस स्टैण्ड, मॉल, ऑटो स्टैण्ड निर्माण, रहने की अच्छी सुविधा व अन्य गतिविधियों के साथ–साथ छोटे–छोटे स्थानीय मन्दिरों के विकास के कार्य किए जाएं।	शहरी विकास/ भाषा कला एवं संस्कृति/ पर्यटन विभाग
16	निर्वाचन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए नदौन तथा ज्वालामुखी के भडौली में व्यास नदी में वाटर स्पोर्टस, रिवर राफ्टिंग इत्यादि का प्रोजेक्ट पर्यटन विभाग के माध्यम से चलाया जाए।	पर्यटन / पर्वतारोहण खेल संस्थान विभाग
6. श्री यादिविन्द्र गोम्मा, जयसिंहपुर		
1.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
2.	सिवील अस्पताल जयसिंहपुर 50 बिस्तर स्वीकृत हुआ था, भवन तैयार है इसमें लिफट, ट्रांसफार्मर, पानी इत्यादि की मूलभूत सुविधाओं का सुचारू संचालन करने के साथ–साथ डाक्टरों व स्टाफ नर्सो के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3.	पीएचसी लम्बागांव के पुराने भवन को गिराकर नये भवन का निर्माण किया जाए तथा पीएचसी मुलग में लैब तकनीशियन की नियुक्ति की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	सीएचसी पंचरूखी को सीएचसी में स्तरोन्नत करने की जो अधिसूचना रदद की गई है उसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	बरसात के मौसम में हुए नुकसान का अनुमान लगभग 32 करोड़ रू0 आंका गया था जो कम है लोक निर्माण विभाग के रिलीफ फण्ड में बढ़ोतरी कर और बजट प्रदान किया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त
6.	भवराना से चुन्गादेवी राज्य सड़क को भी बरसात में भारी नुकसान हुआ है इसके लिए भी बजट उपलब्ध किया जाए।	लोक निर्माण/ राजस्व विभाग/ उपायुक्त
7.	शिवनगर से परागे रा गलू सड़क का निर्माण पीएमजीएसवाई में किया गया था अब इसे सीआरएफ या केन्द्र से अन्य माध्यम के द्वारा पुनः बढ़ती आबादी, वाहनों को ध्यान मे रखकर निर्मित/सुदृढ़ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	परिवहन विभाग के डिपो जयसिंहपुर को अपग्रेड कर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट का प्रावधान किया जाए।	परिवहन विभाग
9.	एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ के आवासीय भवनों का निर्माण एक ही स्थान पर करने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए जिसके लिए भूमि भी उपलब्ध है ।	राजस्व/ग्रामीण विकास विभाग/ सामान्य प्रशासन
10	जल शक्ति विभाग में जल सहायक नियुक्त हैं लगभग 25–30 लोग हैं इन्हें विभाग में मर्ज किया जाए।	जल शक्ति विभाग
11	जल शक्ति विभाग का डिवीजन जयसिंहपुर में खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ सामान्य प्रशासन
12	कलैहण पानी की योजना के परकुलेशन वैल, बाढ़ तथा खनन से प्रभावित हुए हैं तथा खतरे के निशान पर हैं जिसके लिए लगभग 18 करोड़ रू0 का आंकलन /मूल्यांकन विभाग द्वारा किया गया है इसमें अभी तक केवल 75 लाख रू0 मिले हैं,	जल शक्ति विभाग

	इन परकुलेशन वैलों तथा स्कीमों के सुधार/सुदृढ़ीकरण करने के लिए और बजट प्रदान किया जाए।	
13	कंवर दुर्गाचन्द मैमोरियल कॉलेज में सभी संकायों के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों को भरा जाए।	शिक्षा विभाग
14	कॉलेज जयसिंपुर में बीसीए और पीजीडीसीए की क्लासें चलाई जाएं।	शिक्षा विभाग
15	राजीव डे बोर्डिंग स्कूल क्षेत्र में खोला जाए जिसके लिए लगभग 220 कनाल भूमि भी उपलब्ध है।	शिक्षा विभाग
16	आईटीआई सलयाणा में वर्ल्ड बैंक द्वारा दो नए ट्रेड आरम्भ किए जाने हैं जिसके लिए भवन के एक फलोर लिए रू0 20-30 लाख का बजट उपलब्ध करवाया जाए।	तकनीकी शिक्षा
17	आईटीआई लाहडू में इसी वर्ष से अतिरिक्त ट्रेड (डिजल मैकेनिक, सिलाई बुनाई इत्यादि) चलाए जाएं।	तकनीकी शिक्षा
18	पॉलटेकनिक कॉलेज तलवाड में मैकेनिकल कोर्स इसी वर्ष से आरम्भ किया जाए।	तकनीकी शिक्षा
19	पुलिस थाना पंचरूखी में कैदियों के लए पर्याप्त बैरक, स्टाफ के लिए आवास का निर्माण/प्रबन्ध किया जाए।	पुलिस/ कारागार विभाग
20	पुलिस चौकी आलमपुर के लिए अपना भवन प्रदान किया जाए।	पुलिस विभाग
21	एक बड़ा प्रोजेक्ट लाकर अवैध खनन पर रोक लगाकर व्यास नदी का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
22	क्षेत्र के लोगों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए खडडों के किनारे सिम्पल बारबड वायर लगाई जाए या बारबड वायर लगाने के लिए विधायक निधि से पैसे देने पर विचार किया जाए।	कृषि / योजना विभाग
7. श्री विपिन सिंह परमार, सुलह		
1.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
2.	निर्वाचन क्षेत्र में रदद किए गये जल शक्ति तथा विद्युत विभाग के सर्कल, विद्युत विभाग डिवीजन, अस्थायी से स्थायी की कई पुलिस चौकियां इत्यादि को शीघ्र जनहित में बहाल किया जाए।	जल शक्ति/पुलिस /HPSEBLtd./ समस्त सम्बन्धित विभाग
3.	वर्ष 2024 में शानन हाईडल प्रोजेक्ट की लीज समाप्त हो रही है। इसके बाद यह प्रोजेक्ट हिमाचल के नाम होना चाहिए।	HPPCLtd.
4.	सुभाष तथा ओम हाईडल प्रोजेक्ट तथा अन्य हाईडल प्रोजेक्टों पर वाटर टैक्स लगाने के लिए नीति बनाई जाए।	HPPCLtd.
5.	कृपाल चन्द कूहल, सुभाष तथा ओम हाईडल प्रोजेक्ट से प्रभावित हुई हैं इन्हें दुरूस्त किया जाए। साथ ही एमओयू हस्ताक्षर करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए।	HPPCLtd./ जल शक्ति विभाग
6.	बीबीएमबी एरियर के मुददे को सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती के साथ लड़ा जाए।	HPPCLtd.
7.	परकुलेशन वैलों की सुरक्षा के लिए अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस, खनन विभागों के अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए जाएं।	पुलिस / उद्योग विभाग
8.	स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेजों, पीएचसी, सीएचसी, सीएच आदि में सभी श्रेणी के सभी रिक्त पदों को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9.	आयुर्वेदा के क्षेत्र में भी डाक्टरों के रिक्त पदों को भरा जाए।	आयुर्वेदा विभाग
10	हिमाचल प्रदेश में डाक्टरी की पढ़ाई करने वालों को हिमाचल में ही सेवा करनी होगी की नीति बनाई जाए।	स्वास्थ्य/आयुर्वेदा/ सम्बन्धित विभाग
11	जीएसटी का दायरा बढ़ाने के लिए गलत तरीके से कमाई करने वालों पर रोक लगाई जाए।	आयकर विभाग

12	राज्य शीर्ष के तहत डूहक से बैरघटा पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8. श्री पवन कुमार काजल, कांगड़ा		
1.	जल शक्ति विभाग का डिवीजन कांगड़ा खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है इसे बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	सब–सेन्टर रानीताल को पीएचसी करने, तकीपुर पीएचसी को सीएचसी, सब–सेन्टर राजल को पीएचसी, गालियां सब–सेन्टर को पीएचसी, करने की अधिसूचना रदद की गई है इसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	तरसूह कोट को जोड़ने वाले आर.ओ.बी. का शीघ्र निर्माण किया जाए।	लो०नि० विभाग
4.	महिला मण्डलों को विधायक निधि से दी जाने वाली धनराशि से सामान क्रय करने पर बिल इत्यादि प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए।	योजना विभाग
5.	दिनांक 12–08–2022 को मांझी खडड में आई बाढ़ के कारण चैतडू से देहरियां तक साथ लगते क्षेत्र में बर्बाद हुई कूहलों को पुनः बनाया जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम एक पूर्ण सुविधा सहित हाईटैक अस्पताल होना चाहिए।	स्वास्थ्य विभाग
7.	प्रदेश के साथ–साथ जिला कांगड़ा में हैण्डपम्प लगाने पर लगी रोक को हटाया जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	प्रदेश के आवारा पशुओं से क्षेत्र की जनता को निजात दिलाई जाए।	पशु पालन विभाग
9.	कृषि उपकरण ड्रिलर, पॉवर टिल्लर इत्यादि पर सबसिडी की समस्या (किसी एक ही दुकान से खरीदो, मूल्य से अधिक की कोटशन मांगना आदि) को हल किया जाए।	कृषि विभाग
9. श्री केवल सिंह, शाहपुर		
1.	प्रताप सिंह कैरो आईटीआई शाहपुर को आधुनिक आईटीआई के रूप में जाना जाता है इसे स्तरोन्नत कर इंजिनीयरिंग कॉलेज बनाया जाए तथा इसमें professional and job oriented degree courses ही चलाए जाएं।	तकनीकी शिक्षा विभाग
2.	शाहपुर बाजार जोकि पठानकोट–मण्डी फोरलेन में आ गया है इसमें अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को फैक्टर–2 के अन्तर्गत मुआवजा प्रदान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	डंपिंग साईट सुधेड़ को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए तथा कचरे के निपटान हेतु कूड़ा निपटान संयंत्र स्थापित कर विद्युत या अन्य उपयोग में लाया जाए।	शहरी विकास विभाग
4.	धर्मशाला से नडडी होते हुए सतोवरी–बरनेट–घेरा सड़क को पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	पर्यटन की दृष्टि से ट्रैक रूटस करेरी, खब्बरूनाला वाटर फाल हारबोह तथ डलझील का सुधार /विस्तार/सुदृढ़ीकरण तथा सौन्दर्यकरण किया जाए।	पर्यटन विभाग
6.	घेरा से आगे बोंदू–खडीबेही–करेरी–नोहली–कुठारना–सल्ली के लिए बस योग्य सड़क का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	मांवां पुल का निर्माण कार्य अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाकर शीघ्र पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	शाहपुर के गोरड़ा में JICA office को शीघ्र चालू किया जाए।	कृषि/ उद्यान विभाग
9.	शाहपुर नगर पंचायत को पेयजल व्यवस्था प्रदान करने के लिए लम्बित डीपीआर को शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति / शहरी विकास विभाग

10	चम्बी खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग
11	सब्जी मण्डी गोरड़ा में खोली जाए।	कृषि विपणन बोर्ड
12	झुलाड़ नामक स्थान में लगभग 210 कनाल भूमि पर एग्रीकलचर फार्म है इसमें स्वीकृत पदों को बहाल कर भरा जाए।	कृषि विभाग
13	शाहपुर अस्पताल के अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
14	शाहपुर में उद्योग स्थापित किये जाएं।	उद्योग विभाग
15	सैनिकों के लिए शाहपुर में ईसीएचसए, सीएसडी कैन्टीन, रेस्ट हाउस बनाने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए।	उपायुक्त कांगड़ा/ राजस्व विभाग
16	बन्द की गई दो मुद्रिका बसों तथा एक कोटला गुडगांव बस सेवा को बहाल किया जाए।	परिवहन विभाग
17	प्रमुख अभियन्ता प्रोजेक्ट का जो कार्यालय कांगड़ा से मण्डी ले जाया गया है इसे पुनः कांगड़ा वापिस लाया जाए।	जल शक्ति विभाग
18	वन विभाग का आरपीडी का कार्यालय भी कांगड़ा से सोलन ले जाया गया है इसे पुनः कांगड़ा वापिस लाया जाए।	वन विभाग
19	बोह क्षेत्र में लगभग 10 लोगों की जान गई, लोग बेघर हुए उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।	उपायुक्त कांगड़ा
20	क्षेत्र के लिए बल्ह–नडडी–करेरी–खड़ीबोही रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
21	नडडी मे ईको पार्क का निर्माण किया जाए।	वन/ पर्यटन विभाग
22	बीडीओ कार्यालय शाहपुर के पुराने भवन को तोड़कर नये भवन का निर्माण किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
23	सभी माननीय विधायकों को स्थानीय स्तर कोटर्मिनंस स्टाफ तथा बैठने के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही जब कोई विधायक किसी अधिकारी को यदि किसी मामले में कॉल करता है तो उसे वापिस उत्तर मिलना चाहिए।	सामान्य प्रशासन
24	एसडीएम कार्यालय शाहपुर में पानी तथा बिजली की सुचारू व्यवस्था के लिए उपायुक्त के माध्यम से उपयुक्त धनराशि जारी जाए।	उपायुक्त
25	राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कोचिंग सेन्टर (मेडिकल इन्जीनियरिंग/ सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु) स्वीकृत किया जाए तथा अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जाए।	शिक्षा विभाग
26	राजकीय महाविद्यालय लन्ज में पानी तथा बिजली की सुचारू व्यवस्था के लिए उचित धनराशि का प्रावधान किया जाए।	शिक्षा विभाग
27	निर्वाचन क्षेत्र शाहपुर की सूखाहार सिंचाई परियोजना का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।	जल शक्ति विभाग
28	शाहपुर को ट्राउट हब (मतस्य क्षेत्र के रूप में) बनाने के लिए उचित कार्य किया जाए जिसके लिए क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में ट्राउट सेन्टर भी उपलब्ध हैं।	मतस्य विभाग
29	बन्द की गई बस सेवाओं कोटला–शाहपुर–कांगड़ा दिल्ली, कोटला–शाहपुर–कांगड़ा–हरिद्वार तथा कांगड़ा–शाहपुर–कांगड़ा–बददी का पुनः संचालन किया जाए।	परिवहन विभाग
30	शाहपुर क्षेत्र के कलियाड़ा तथा रजोल में ओबीसी भवन निर्माण कार्य के लिए उचित धनराशि का प्रावधान किया जाए।	SOMA
31	शाहपुर में आईटी पार्क स्थापित किया जाए।	IT Deptt.
32	धरकण्डी क्षेत्र में पर्यटन विभाग का होटल खोला जाए।	पर्यटन विभाग

10.	श्री सुधीर शर्मा, धर्मशाला	
1.	क्षेत्र की तीन खडडों चराण, मांझी तथा मनूणी से नुकसान न हो इसके लिए रू0 30-35 लाख का प्रबन्ध किया जाए, ताकि शेष धनराशि को केन्द्र के माध्यम से स्वीकृत किया जा सके ।	जल शक्ति विभाग
2.	अमृत मिशन के तहत पेयजल योजना बैजनाथ का निर्माण किया गया है जिसके लिए गलती से दोबारा पैसा आया है इसे वापिस किया जाए।	शहरी विकास विभाग
3.	जल शक्ति विभाग का सब डिवीजन टंग में तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यालय खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
4.	विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत मांझी से धर्मकोट तथा ट्यूलिप गार्डन से चटकर रोपवे का निमार्ण किया जाए।	RTDC
5.	ईलैक्ट्रिकल बसों के साथ-साथ हाईड्रोजन से चलने वाली बसों पर भी विचार किया जाए।	परिवहन विभाग
6.	धर्मशाला में एयरपोर्ट के साथ लगते हिमुडा के प्लाट को बेचने पर रोक लगाई जाए ताकि यहां पर एग्जिबीशन ईन्डस्ट्ररी हब का निर्माण किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।	पर्यटन विभाग/ हिमुडा
7.	बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के बीड़ बिर्लीग में पैराग्लाईडिंग की एक साईट पर एक छोर से दूसरे छोर तक रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
6.	जिला सोलन	
1.	श्री के. एल. ठाकुर, नालागढ़	
1.	विभाग द्वारा नालागढ़-रामशहर-शिमला सड़क की दयनीय स्थिति को ठीक किया जाए या इसे केन्द्र के माध्यम से सीआरएफ में शामिल कर इसका सुधार/सुदृढ़ीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2.	सोबन माजरा-कांशीपुर-बरूना-दिओली सड़क का सुधार/ सुदृढ़ीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	पंजैहरा में जल शक्ति या लोक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस बनाया जाए।	लोक निर्माण/जल शक्ति विभाग
4.	राजकीय महाविद्यालय रामशहर तथा बरूना के भवन निर्माण हेतु उचित बजट प्रावधान कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग
5.	आईटीआई कवारन (कनौला) के लिए उचित बजट प्रावधान कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
6.	गॉंव की सड़कों तथा मेजर सड़कों में 30 एमएम तथा 40 एमएम का प्रयोग किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	लिंक सड़क निर्माण में 3.75 मीटर चौड़ाई का नियम अपनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	सिंचाई की योजनाओं में सीएडी (Command Area Dev.) प्रोजेक्ट में बजट का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
9.	बीबीएनडीए के अधीन क्षेत्र में विकास के लिए लगभग 50-60 करोड़ बजट का प्रावधान किया जाए।	शहरी विकास / उद्योग विभाग
10	लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त बनाई गई सड़कों की मुरम्मत/रख-रखाव के लिए बजट की उचित व्यवस्था की जाए।	लोक निर्माण/ ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभाग
11	प्रदेश में विद्यमान उद्योगों में 70 प्रतिशत हिमाचल के लोगों को रोजगार देने की नीति को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही इनके वेतन की समस्या को भी हल किया जाए।	उद्योग/श्रम एवं रोजगार विभाग

12	बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई तथा पेयजल की योजनाओं में उपयोग होने वाली पाईपों में इस्तेमाल हो रहे वर्तमान डाऐ (Dia) के एमएम में बदलाव कर इसे बढ़ाया जाए। साथ ही सिंचाई की योजनाओं में मेन इनलेट से लेकर आउटलेट तक की वितरण प्रणाली (पूर्ण डिजाईन) में भी डाऐ में बदलाव के साथ सुधार किया जाए।	जल शक्ति विभाग
13	जेजेएम या अन्य माध्यम से लगे नलों की लाईनों को भूमिगत किया जाए।	जल शक्ति विभाग
14	रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने बारे विभाग बजट प्रावधान कर कार्य आरम्भ करे।	जल शक्ति विभाग
15	नालागढ़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
16	नालागढ़ में नए बस रूटस प्रदान किए जाएं।	परिवहन विभाग
17	नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस विभाग का सुदृढ़ीकरण किया जाए या अतिरिक्त पुलिस बल क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाए।	पुलिस विभाग
18	अवैध खनन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।	उद्योग विभाग
19	नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में फ्रूट तथा सब्जी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाए।	कृषि/ उद्यान विभाग / Marketing Board
20	विद्युत विभाग में तारों को Built up area से बदलने बारे उचित बजट का प्रावधान किया जाए।	HPSEBLtd./ HPTCLtd.
21	नालागढ़–दभोटा–बोदला–टिब्बी–पटेर फालू–अन्दोला–कश्मीरपुर बघेरी–खातीवल–गड़ामौड़ा सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग में स्तरोन्नत कर इसका सुधार/सुदृढ़िकरण/विस्तार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
22	नए खोले गये बीडीओ कार्यालय रामशहर, पीएचसी डोली, पन्जैहरा तथा अपग्रेड किए गये सीएचसी जोघों तथा 200 बिस्तर सीविल अस्पताल की रदद की गई अधिसूचनाओं को जनहित में बहाल किया जाए।	ग्रामीण विकास/ स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
2. श्री विनोद सुल्तानपुरी, कसौली		
1.	कसौली में जाम की समस्या को हल करने के लिए गडखल से कसौली के लिए लगभग 28 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाए जिसके लिए आर्मी से भी बजट प्राप्त किया जा सकता है ।	लोक निर्माण विभाग
2.	पर्यटन की दृष्टि से कसौली में लंदन की तर्ज पर Giant Wheel का निर्माण किया जाए।	पर्यटन विभाग
3.	कैन्टोनमेंट एरिया से सीविल एरिया को बाहर किया जाना है राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ इस पर गम्भीरता से निर्णय करे। साथ ही 100 से अधिक वर्षो से इस क्षेत्र में रह रहे लोगों की सभी समस्याओं (भूमि खरीद, मकान मुरम्मत, पक्के रास्ते इत्यादि) को हल किया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त सोलन
4.	नाहन सड़क से आगे जौहड़जी से मल्ला सड़क पिंजौर निकलती है इसे राज्य शीर्ष या केन्द्र के माध्यम से 5 मीटर चौड़ाई का बनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5.	सुबाथु कॉलेज को सरकार ने अपने अधीन लिया है इसके स्टाफ की समस्या को हल किया जाए।	शिक्षा विभाग
6.	टिम्बर ट्रेल क्षेत्र के पास में कौशल्या बॉंध का निर्माण कर इसके ऊपर से सड़क का भी निर्माण किया जाए जिससे पानी की सुविधा भी लोगों को प्राप्त होगी और सड़क दूरी भी कम होगी साथ ही पर्यटन का भी विकास होगा।	जल शक्ति/ लोक निर्माण विभाग

7.	नकदी फसल में बढ़ोतरी करने के लिए 100–200 है0 के स्थान पर 1000 से 2000 प्रति है0 भूमि प्रस्तावित किया जाए इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।	कृषि विभाग
7. जिला बिलासपुर		
1. श्री जीत राम कटवाल, झण्डूता		
1.	सीर खडड पर डैम बनाने की डी.पी.आर. को शीघ्र केन्द्र से स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
2.	गुग्गा गेहड़वीं के पास छमाण नामक स्थान पर सुरंग का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	ज्योरिपतन–स्वारघाट रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
4.	किरतपुर से बागछाल के साथ कोटधार की खाली भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए।	उद्योग विभाग
5.	निर्वाचन क्षेत्र के लिए 132 के.वी. सब–स्टेशन के लिए 15–18 बीघा भूमि सुन्हाणी में उपलब्ध है शीघ्र इसके कार्य को आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPSEBLtd.
6.	विद्युत विभाग का डिवीजन झण्डूता में खोला जाए।	HPSEBLtd.
7.	मिनी सचिवालय झण्डूता के निर्माण हेतु उचित बजट की व्यवस्था कर कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	राजस्व विभाग
8.	निर्वाचन क्षेत्र में डिनाटीफाई किए गए संस्थानों को पुनः बहाल किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग/ सामान्य प्रशासन
9.	निर्वाचन क्षेत्र के बरठीं, तलाई से बस सेवाएं आरम्भ की जाएं।	परिवहन विभाग
10	प्रदेश के गरीब भूमिहीन परिवारों ने सरकारी 2–3 बिस्वा भूमि पर मकान बनाएं है इन्हे नियमित करने के लिए कमेटी का निर्माण किया जाए तथा शीघ्र इनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए।	वन / राजस्व विभाग
11	सब–तहसील शहतलाई और पटवार सर्कल मलरौण (Malraon) को खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
12	जल शक्ति सब–डिवीजन शहतलाई तथा विद्युत विभाग के सब–डिवीजन जेजवीं को खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ HPSEBLtd./ सामान्य प्रशासन
13	पीएचसी ठाठ्ल, जांगल, चामटा, सीएचसी कलोल तथा गेहड़वीं को खोलने/अपग्रेड करने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
2. श्री राजेश धर्माणी, घुमारवीं		
1.	प्रदेश में मैकेनाईजड़ स्लाटर हाउसों का निर्माण किया जाए जिसके लिए एपीडा से भी फण्ड प्राप्त किए जा सकते हैं।	पशु पालन विभाग
2.	माता नैनादेवी जी तथा बाबा बालक नाथ मन्दिर के बीच की सड़क दूरी को कम करने के लिए गोविन्द सागर झील पर केबल फैरी रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
3.	हिमाचल प्रदेश फल उत्पादक प्रदेश है लेकिन यहां का अधिकतर फल बर्बाद होता है। इसे बर्बादी से बचाने के लिए प्रदेश में फलों से शराब बनाने की नीति बनाई जाए।	उद्यान/ आयकर विभाग
4.	प्रदेश के अनाथ, अपंग, विधवाओं की मकान बनाने के लिए अलग श्रेणी निर्मित की जाए। साथ ही डैहर अनाथ आश्रम का सुधार/विस्तार किया जाए।	SOMA/ महिला बाल विकास विभाग
5.	प्रदेश के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों को रेशनेलाईज किया जाए।	शिक्षा/स्वास्थ्य विभाग
6.	भवन निर्माण सामग्री (क्रशर) में मूल्य एक समान होना चाहिए।	उद्योग विभाग

7.	सरकार की आने वाली गोबर खरीद योजना में वर्मी कम्पोस्ट को भी शामिल किया जाए तथा स्थानीय स्तर पर कलेक्शन सेन्टर निर्मित किए जाएं।	पशु पालन/कृषि विभाग
8.	सीवरेज योजनाओं को प्रदेश में बड़े पैमाने पर निर्मित किया जाए क्योंकि गॉंव भी अब शहरों के रूप में विकसित हो रहे हैं।	जल शक्ति/शहरी विकास विभाग
9.	प्लाईवुड इन्डस्ट्री, बैम्बो इन्डस्ट्री को प्रदेश में स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।	उद्योग/वन विभाग
10	खैर को बेचने के लिए लगने वाली एक्सपोर्ट फीस को समाप्त किया जाए।	वन विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र मे औद्योगिक ईकाई विकसित करने के साथ–साथ मुख्यमंत्री स्वावलम्बन पार्क का निर्माण किया जाए।	उद्योग विभाग
12	क्षेत्र में प्रोफेशनल कलस्टर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए।	शिक्षा विभाग
13	नए खोले गए राजकीय महाविद्यालय में नए कोर्स स्वीकृत किए जाएं ।	शिक्षा विभाग
14	क्षेत्र में विद्यमान कम्बाईन्ड ऑफिस भवन निर्मित किया गया है जिसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए इस भवन को अन्य गतिविधियों पार्किंग, हॉल, कॉन्फ्रन्स हॉल, आवासीय इत्यादि के लिए चालू किया जाए।	शहरी विकास विभाग/ उपायुक्त
15	सड़को को अपग्रेड किया गया है जो कि ठीक प्रकार से नहीं हुई हैं इन्हें गुणवत्ता के साथ अपग्रेड किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
16	औहर में टूरिस्ट कॉम्पलैक्स का निर्माण किया जा रहा है, हैलीपोर्ट भी बनना है, होटल/फूड कोर्ट जिसके लिए और भूमि चाहिए जिसकी अनापत्ति पर्यटन विभाग को प्रदान की जाए।	कृषि/पर्यटन विभाग
17	प्रदेश के सभी लोगों को स्थानीय स्तर पर न्याय मिलना चाहिए।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता / पंचायती राज विभाग
3. श्री त्रिलोक जम्वाल, बिलासपुर		
1.	सीमेन्ट फैक्ट्री विवाद का शीघ्र समाधान किया जाए।	उद्योग विभाग
2.	निर्वाचन क्षेत्र में संस्थानों को खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई हैं उन्हें बहाल किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग / सामान्य प्रशासन
3.	उप–तहसील हरलोग को भी बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
4.	पुलिस चौकी एम्स को बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग/ सामान्य प्रशासन
5.	सभी माननीय विधायकों को स्थानीय स्तर कोटर्मिनंस स्टाफ तथा बैठने के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाया जाए।	सामान्य प्रशासन
6.	गॉंव की छोटी–छोटी सड़कें जो बरसात के कारण बन्द पड़ी हैं इन्हें खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	प्रदेश की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जनता को सड़क, पानी, बिजली, उद्योग, बड़े प्रोजेक्ट इत्यादि की सुविधा प्रदान करने के लिए वन विभाग में एफसीए/एफआरए की अनापत्ति का सरलीकरण किया जाए।	वन विभाग
8.	कोलडैम तथा गोविन्दसागर रिजरवायर से पानी उठाने की क्षमता में बढ़ोतरी की जाए ताकि स्थानीय जनता को पेयजल तथा सिंचाई के लिए उचित पानी मिल सके। साथ ही यदि कोलडैम योजना के टैंकों का पानी ओवर फलो होता है तो पानी के एक टैंक को दूसरे स्थानीय टैंकों के साथ कनेक्ट/जोड़ा जाए ताकि	जल शक्ति/ वन विभाग/ सामान्य प्रशासन

	पानी व्यर्थ न बहे और दूसरे टैंक में शिफ्ट हो जाए जिससे पानी की समस्या का समाधान हो सकता है।	
9.	बिलासपुर जिला में 1400 करोड़ रू0 के प्रोजेक्ट को शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPTCLtd.
10	औहर होटल के साथ रू0 103–104 करोड़ की लागत से बनने वाले बझ्वानी पुल का निर्माण कार्य तीव्रगति के साथ शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
11	भानुपली–बिलासपुर रेल लाईन में बिलासपुर से बरमाणा तक की भूमि को शीघ्र अधिग्रहित कर उचित मुआवजा लोगों को प्रदान किया जाए।	परिहवन विभाग
12	निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर के छोटे–छोटे कस्बों में लो वोल्टेज की समस्या, सड़क के साथ दुकानों तथा साथ लगते एरिया में बिजली की तारों के स्थान पर ओवरहैड केबल का प्रयोग किया जाए।	HPSEBLtd.
13	आईटीआई के स्थान पर सीनियर सकैण्डरी स्कूलों में ही तकनीकी शिक्षा के विषय चलाए जाएं।	तकनीकी शिक्षा/ शिक्षा विभाग
4. श्री रणधीर शर्मा, श्री नैना देवी जी		
1.	पुलिस चौकी एम्स बिलासपुर को पुनः अधिसूचित किया जाए।	पुलिस विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	4–5 पटवार सर्कल को पुनः अधिसूचित किया जाए।	राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	3–4 पी.एच.सी. को पुनः अधिसूचित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
4.	नैनादेवी जी शक्तिपीठ को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए ट्रस्ट की ओर से कुछ नए कार्य किए जा रहे थे जैसे लिफ्ट लगाना, गोविन्द सागर झील की तरफ ग्लास पुल, सैल्फी प्वाईंट इत्यादि जो बन्द पड़े हैं इन्हें चालू किया जाए।	पर्यटन विभाग
5.	33 के.वी. सब स्टेशन नैनादेवी जी के कार्य को तीव्रगति से पूरा किया जाए।	HPSEBLtd.
6.	नैनादेवी जी तथा बाबा बालकनाथ मन्दिरों को आपस में जोड़ने के लिए केबल फैरी या वैकल्पिक सड़क मार्ग का निर्माण किया जाए।	RTDC/ लोक निर्माण विभाग
7.	ग्वालठाई में विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाए तथा नए क्षेत्र नंदबैला को भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।	उद्योग विभाग
8.	टिम्बर, बॉंस, कृषि तथा बागवानी आधारित उद्योगों को स्थापित कर क्षेत्र का विकास किया जाए।	उद्योग विभाग
9.	पानी की समस्या को हल करने के लिए भाखड़ा के नीचे औरिण्डा के पास से बन रहे प्रोजेक्ट को तीव्रगति से पूरा किया जाए तथा कोलडैम से जुखाला के ऊपरी क्षेत्रों के resources charge करने के लिए उठाऊ योजना प्रोजेक्ट को केन्द्र के माध्यम से शीघ्र स्वीकृत करवार कार्य आरम्भ किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10	पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र की झीलों में वाटर स्पोर्टस को बढ़ावा देकर क्षेत्र का विकास किया जाए।	पर्यटन विभाग
11	गोविन्दसागर झील के लिए निर्मित सभी कच्ची सड़कों को पक्का किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
12	कठवौल धार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
13	सीमेंट प्लांट बन्द चल रहे हैं ट्रांसपार्टरों को ट्रांसपोर्ट सबसिडी की नीति प्रदान करने बारे सरकार विचार करे।	उद्योग विभाग

14	उपायुक्त महोदय के पास केन्द्र से आया Disaster Management Fund का पैसा शीघ्र जारी किया जाए।	उपायुक्त बिलासपुर
15	कोरोना में बन्द बस सेवा स्वारघाट से ऊना वाया नैनादेवी जी को पुनः चालू किया जाए।	परिवहन विभाग
16	क्षेत्र में विद्यमान छोटी–छोटी लिंक सड़कों जहां पर बड़ी बसें चलाना व्यवहारिक न हो, वहां पर 15–20 सीट वाली छोटी बसों / टैम्पो को चलाने के लिए बेरोजगार युवाओं को परमिट प्रदान किए जाएं।	परिवहन विभाग
17	स्वास्थ्य के क्षेत्र में पी.एच.सीज. तथा सी.एच.सीज. में डॉक्टरों के साथ अन्य स्टाफ के स्वीकृत पदों को पूर्ण रूप से भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
18	प्रदेश में हरित क्रान्ति लाने या इसे हरित राज्य बनाने के लिए 2023–24 केन्द्रीय बजट से लाभ उठाया जाए।	कृषि विभाग
19	खैर के साथ–साथ जंगलों में विद्यमान जड़ी बूटियों से राजस्व प्राप्त करने के लिए विभाग विशेष नीति का निर्माण करे।	वन विभाग
20	विद्युत विभाग में खम्बों तथा तारों को बदलने के लिए विभाग में अलग से बजट का प्रावधान किया जाए।	HPSEBLtd.
8. जिला मण्डी		
1. श्री दीप राज, करसोग		
1.	बखरौड़–सुनारली–केलोधार–लुहरी–शिमला सड़क का सुधार/ सुदृढ़ीकरण किया जाए क्योंकि यह सड़क सभी धार्मिक स्थलों से गुजरती है जिससे क्षेत्र मे पर्यटन का विकास होता है।	लोक निर्माण विभाग
2.	तत्तापानी से मण्डी वाया बखरौड सड़क को एमडीआर सड़क या राष्ट्रीय उच्च मार्ग में शामिल कर इसका सुधार/ सुदृढ़ीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	करसोग अस्पताल के लिए सीटी स्कैन की 64 स्लाईसिज़ की आधुनिक मशीन उपलब्ध करवाई जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए सोलर पैनल/सिस्टम का अधिक प्रयोग किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	शिक्षा के क्षेत्र को सुद्वढ़ करने के लिए करसोग में अच्छा केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।	शिक्षा विभाग
6.	करसोग–दिल्ली वोल्वो बस सेवा आरम्भ की जाए।	परिवहन विभाग
7.	करसोग बस अडडे के पुराने भवन का जीर्णोद्धार किया जाए ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके।	बस अडडा प्राधिकरण
8.	महादेव मन्दिर के साथ ग्राम पंचायत में एक ईको टूरिज्म पार्क का निर्माण किया जाए।	पर्यटन विभाग
9.	करसोग में Soil Testing Lab खोली जाए।	Soil Conservation/ कृषि विभाग
10	तत्तापानी में पुलिस चौकी खोली जाए।	पुलिस विभाग
11	डीएसपी कार्यालयों में कॉलट्रेस करने की सुविधा के साथ–साथ अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस कर इनका सुदृढ़ीकरण किया जाए।	पुलिस विभाग
12	करसोग में हैलीपैड बनाया जाए।	पर्यटन विभाग
13	प्रदेश के सैल्फ हैल्प ग्रुपस को एचटीपीआई के साथ जोड़कर इनके उत्पादों को ऑनलाईन बेचा जाए।	IT Deptt./ ग्रामीण विकास विभाग
2. श्री राकेश कुमार, सुन्दरनगर		
1.	1952 की अस्थाई पुलिस चौकी डैहर को स्थायी करने की अधिसूचना को रदद किया गया है इसे बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग / सामान्य प्रशासन
2.	पीएचसी बन्दली, पौड़ा कोठी तथा हैल्थ सब–सेन्टर खोलने/स्तरोन्नत करने की अधिसूचनाएं रदद की गई हैं इन्हें बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन

3.	जल शक्ति विभाग में सब–डिवीजन कांगू खोलने की अधिसूचना को रदद किया गया है इसे बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ सामान्य प्रशासन
4.	पशु औषधालय खोलने/स्तरोन्नत करने की अधिसूचना को रदद किया गया है इसे बहाल किया जाए।	पशु पालन विभाग / सामान्य प्रशासन
5.	10 बिस्तर आयुर्वेदिक अस्पताल सुन्दरनगर की अधिसूचना को रदद किया गया है इसे बहाल किया जाए।	आयुर्वेदा विभाग/ सामान्य प्रशासन
6.	निहरी पुलिस चौकी को थाना बनाया जाए।	पुलिस विभाग
7.	सुन्दरनगर नगर परिषद के पूरे क्षेत्र में बिजली की तारों को भूमिगत करने के कार्य को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	शहरी विकास विभाग/ HPSEBLtd.
8.	सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र में सलापड़ से तत्तापानी के रूट पर जैटी तथा पास के स्थानों क्याण, करला, दोगरी तथा हाड़ाबोई में भी तीन–चार आधुनिक किस्म की जैटी का प्रबन्ध पर्यटन विभाग या NTPC से करवाया जाए।	पर्यटन विभाग/ HPPCLtd.
9.	सुन्दरगर के सुकेत में झील के किनारे कैफे चल रहा है जहां पर दो कमरे भी हैं। इस कैफे के विस्तारीकरण के लिए Convention Hall के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रू0 का ऐस्टीमेट तैयार किया गया है इसे शीघ्र मंजूर कर कार्य आरम्भ किया जाए। इसमें 10 कमरे, पार्किंग, हॉल इत्यादि के निर्माण की व्यवस्था है।	पर्यटन विभाग
10	एनएच–21 के साथ कलौड़–कपाही–खिलड़ा सड़क पर लगभग 30 मीटर का पुल बना है जिससे बहुत जाम लगता है इसलिए बीबीएमबी के साथ मिलकर यहां पर एक और पुल का निर्माण किया जाए। जिससे आने व जाने के लिए अलग–अलग इस्तेमाल करने से जाम नहीं लगेगा और कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा।	लो0नि0 विभाग/ HPPCLtd.
11	कोलडैम बनने से पैदल पुल डूब गया था इसके स्थान पर धनयारा पंचायत के गॉंव करला से जिला सोलन के गॉंव बेरल के लिए नये पैदल पुल का निर्माण किया जाए।	लो0नि0 विभाग/ HPPCLtd.
12	निहरी के अस्थायी हैलीपैड जो सड़क से भी जुड़ा है, का स्थायी तौर पर निर्माण किया जाए।	पर्यटन विभाग
13	नगर परिषद सुन्दरनगर में कार्यकारी अधिकारी के रिक्त पद को शीघ्र भरा जाए।	शहारी विकास विभाग
14	पुंग–घांगणु–तलेली–डैहर सड़क की डीपीआर को भारतमाला में स्वीकृत कर शीघ्र इसका कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
15	इन्डोर स्टेडियम सुन्दरनगर के कार्य को पूर्ण करने के लिए बजट की व्यवस्था कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग
16	लोक निर्माण विश्राम गृह सुन्दरनगर के कार्य को पूर्ण करने के लिए बजट की व्यवस्था कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
17	सीनियर सकैण्डरी स्कूल तलेली के नए भवन निर्माण के लिए टैण्डर प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
18	मेडिकल कॉलेज सुन्दरनगर में ट्रामा सेन्टर लेवल–2 तथा कैन्सर अस्पताल निर्माण की प्रस्तावना शीघ्र केन्द्र सरकार को भेजकर इसे स्वीकृत करवाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
19	पंडोह, सलापड़ तथा सुन्दरनगर में बीबीएमबी द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं वहां पर अध्यापकों के पदों को पूर्ण रूप से भरकर कक्षाएं चलने दी जाएं।	शिक्षा विभाग/ HPPCLtd.
20	निर्वाचन क्षेत्र में शिलान्यास/पटटिकाएं तोड़ी गई हैं उन्हें सम्बन्धित विभाग पुनः उसी स्थान पर स्थापित करे और पुलिस विभाग ऐसे दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।	पुलिस/ सम्बन्धित/ लोक निर्माण/ जल शक्ति विभाग

21	पर्यटन को ध्यान में रखते हुए शिमला से कुछ मुख्य कार्यालयों को सुन्दरनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र या साथ लगते विधान सभा क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाए। क्योंकि शिमला एक पर्यटक स्थल है और जाम भी ज्यादा रहता है।	समस्त सम्बन्धित विभाग/ सामान्य प्रशासन
3. श्री विनोद कुमार, नाचन		
1.	पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र के विकास के लिए देवीदढ़, कमरूनाग, शिकारी, डाबरूद्धार, मशोगल, लुट्टापुखर झुग्गी, सुरवा जाल्पा माता मन्दिर इत्यादि स्थानों को पयर्टन की दृष्टि से और अधिक विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
2.	देवीदढ़ को मिनी खजियार कहा जाता है वहां तक पहुंचने वाली सड़क को चौड़ा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3.	मां शिकारी माता मन्दिर के लिए चैल चौक से सड़क निकाली गई है शीघ्र मै0/टा0/सुदृढ़िकरण/विस्तार/सुधार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	ज्यूणी खडड में वाटर स्पोर्टस गतिविधियों को विकसित किया जाए।	पर्यटन/पर्वतारोहण खेल विभाग
5.	ग्रेविटी की स्कीमों के लिए बफर स्टोरेज टैंकों के निर्माण की डीपीआर को स्वीकृत कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा करें।	जल शक्ति विभाग
6.	किसानों को कृषि हेतु सिंचाई की सुचारू व्यवस्था प्रदान की जाए।	कृषि / जल शक्ति विभाग
7.	विधायक निधि की अन्तिम किश्त को बहाल किया जाए तथा इसे 3 करोड रू0 किया जाए।	योजना विभाग
8.	ऐच्छिक निधि की अन्तिम किश्त को बहाल किया जाए तथा इसे 15 लाख रू0 किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
9.	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
10	चैलचौक से पन्डोह सड़क को एनएच बनाने के लिए भूमि उपलब्ध है इसलिए इसे सीआरएफ में बनाया जाए या एमडीआर में निर्मित किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
11	आउटसोर्स कर्मचारी जिन ऐजैन्सियों के माध्यम से तैनात किए गये हैं कौन कर्मचारी काम कर रहा है कौन नहीं इस पर चैक लगाया जाए साथ ही इन्हें पूरा वेतन मिले इनका शोषण न हो इस पर भी सुधार किया जाए।	सामान्य प्रशासन/ समस्त सम्बन्धित विभाग
12	इन्डोर स्टेडियम राजकीय महाविद्यालय वासा के निर्माण कार्य को तीव्रगति के साथ पूरा किया जाए।	शिक्षा विभाग
13	अटल आदर्श विद्यालय के कार्य को पूर्ण करने के लिए उचित बजट की व्यवस्था कर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही कृषि विभाग की 5 बीघा अतिरिक्त भूमि को शिक्षा विभाग के नाम किया जाए।	शिक्षा/ कृषि/ राजस्व विभाग
14	क्षेत्र के लिए घोषित औद्योगिक क्षेत्र को निर्मित करने सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।	उद्योग विभाग
15	100 बिस्तर सीएच गोहर तथा 35 पंचायतों के लिए सीएचसी चौंक की रदद अधिसूचना को बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
16	बरसात से बहे हुए 6 पुलों (5 वन विभाग+ 1 पंचायत द्वारा निर्मित) को पुनः रिस्टोर किया जाए।	वन/पंचायती राज / लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त
17	धनोटू थाना के सुचारू संचालन हेतु उचित बजट की व्यवस्था की जाए।	पुलिस विभाग
4. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर, द्रंग		
1.	द्रंग विधानसभा क्षेत्र में नौ सड़कें पास हैं उनमें बस सेवाएं आरम्भ या बस रूट एक्सटेन्ड किये जाएं।	परिवहन विभाग

2.	ऊहल तथा व्यास नदी है यहां पर विद्युत के प्रोजेक्ट लगाए जाएं।	HPPCLtd.
3.	गोगरधार, झटिंगरी, बरोट, उतरछाल, पराशर के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
4.	बुबु टनल का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण वि0
5.	द्रंग में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।	शिक्षा विभाग
6.	क्षेत्र में विद्यमान लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों में 2–2 जेसीबी प्रदान की जाएं।	लोक निर्माण वि0
7.	सीएच पधर में रेडियोग्राफर के रिक्त पद को भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
8.	गॉव टिक्कन तथा कटौला में सब्जी मण्डी का निर्माण किया जाए।	कृषि विपणन बोर्ड
9.	एनएच गुम्मा सब–डिवीजन में बेकार पड़े बुलडोजर तथा स्नोकटर लोक निर्माण विभाग के डिवीजन नम्बर–1 को दिए जाएं।	लोक निर्माण वि0
5. श्री प्रकाश राणा, जोगिन्द्रनगर		
1.	प्रोजेक्ट जोल–3 पर 132 के.वी. सब–स्टेशन का निर्माण किया जाए।	HPTCLtd./ HPSEBLtd.
2.	विद्युत विभाग के डिवीजन में 124 पद कर्मचारियों के रिक्त हैं यहां पर कम से कम 20–25 लोगों की मैनपॉवर प्रदान की जाए।	HPSEBLtd.
3.	बरसात के कारण बन्द सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए। साथ ही एनएच के शिफट दफतर से जेसीबी मिलनी थी उसे लोक निर्माण विभाग को दिया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	जल शक्ति विभाग में धीमीगति से चल रहे कार्यों को तीव्रगति से पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	जोगिन्द्रनगर अस्पताल में डाक्टरों की कमी को दूर किया जाए। साथ ही प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों एक अस्पताल ऐसा हो जहां पूरी आधुनिक सुविधाएं पूर्ण स्टाफ, डाक्टरों के साथ प्रदान की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6.	प्रदेश की जनता को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
7.	सब–डिवीजन लोक निर्माण विभाग मकरेड़ी विश्राम गृह में चल रहा था इसकी अधिसूचना रदद की गई हैं इन्हें बहाल किया जाए।	लोक निर्माण विभाग/ सामान्य प्रशासन
8.	पुलिस चौकी लड़भड़ोल को पुलिस थाना बनाने की अधिसूचना रदद की गई है इसे बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग/ सामान्य प्रशासन
9.	पर्यटन की दृष्टि से बीड़ पैराग्लाईडिंग साईट से मन्दिर/पोर्ट/फोर्ट तक रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
10	प्रदेश को वित्तीय स्तर पर मजबूत करने तथा राजस्व बढ़ाने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया जाए।	राजस्व / वित्त विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र के पशु औषधालयों पडोल, तुलाह तथा ऊटपुर को पशु चिकित्सालयों में स्तरोन्नत किया जाए।	पशु पालन विभाग
6. श्री चन्द्र शेखर, धर्मपुर		
1.	प्रदेश में पंचायतों के पास अपनी भूमि रिक्त पड़ी है जिस पर पंचायत भवन निर्माण के साथ अन्य छोटे–छोटे सैल्फ हैल्प ग्रुपज़ जैसे कम्पयूटर सेन्टर, नाई कोर्स, ब्यटीफिकेशन कोर्स पीपीपी मोड पर चलाने के लिए पंचायतों में ही भवनों का निर्माण कर संचालन किया जाए जिससे पंचायतों का सुदृढ़ीकरण होगा व राज्य की आय में भी बढ़ोतरी होगी।	पंचायती राज/ ग्रामीण विकास विभाग/ उपायुक्त
2.	कृषि के क्षेत्र में किसानों को उनकी फसलों को आवारा पशुओं से बचाव हेतु खेतों में बाड़बन्दी करने के लिए उचित बजट सबसिडी सहित प्रदान किया जाए।	कृषि विभाग

3.	सरकाघाट के पुराने बस अडडे को पीपीपी मोड पर प्रदान कर पार्किंग, शॉपिंग कॉम्पलैक्स इत्यादि का निर्माण किया जाए जिससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
4.	रोगी कल्याण समितियों को रिवाईव किया जाए ताकि अस्पतालों का उचित रख–रखाव हो सके।	स्वास्थ्य विभाग
5.	निर्वाचन क्षेत्र के साथ–साथ पूरे प्रदेश के पंचायत घरों में चौकीदार तथा सफाई कर्मचारी की नियुक्ति अनिवार्य की जाए।	पंचायती राज विभाग/ सामान्य प्रशासन
6.	2011–12 का ड्राईविंग स्कूल पपलोग में बनकर तैयार है उपयोग में न होने के कारण इसे अन्य कार्यालयों के उपयोग हेतु प्रदान किया जाए। इसमें सैनिक स्कूल/एनडीआरएफ की यूनिट दी जाए।	परिवहन विभाग/ उपायुक्त
7.	अटल आदर्श विद्यालय के अधूरे कार्य को पूर्ण कर इसका सुचारू संचालन किया जाए।	शिक्षा विभाग
8.	बैम्बू कलेक्शन सेन्टर निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाए।	वन/उद्योग विभाग
9.	निर्वाचन क्षेत्र में रेशम कीट पालन की प्रोसेसिंग यूनिट विद्यमान है बड़े उद्योग के रूप में इसका सुधार/विस्तार किया जाए।	उद्योग विभाग
10	108 एम्बुलैन्स की नीति में सुधार किया जाए। साथ ही यदि कोई एम्बुलैन्स अस्पताल को या 108 ऐजैन्सी को दान करता है तो उसके संचालन की जिम्मेदारी भी 108 की ही सुनिश्चित की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11	जोगिन्द्रनगर–धर्मपुर को जोड़ने वाले लाल बहादुर शास्त्री सेतु/पुल को डबल लेन करने के कार्य को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
12	धर्मपुर क्षेत्र के रिहायशी ईलाकों की खडडों का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
13	धर्मपुर तथा सन्धोल नगर परिषद के लिए मल निकासी की योजनाएं प्रदान की जाएं।	शहरी विकास/ जल शक्ति विभाग
14	कमलाह ईस्ट देव के लिए रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
7. श्री अनिल शर्मा मण्डी		
1.	थाना पलां प्रोजेक्ट (191MW) जो कि 400 मी0 की परिधी में ही तैयार हो सकता है का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	HPPCLtd.
2.	राजीव डे बोर्डिग स्कूलों का निर्माण भौगोलिक (पहाड़ी तथा मैदानी) स्थिति को ध्यान में रखकर पूरी आधुनिक नीति के साथ किया जाए। साथ ही इसमें नियुक्त होने वाले अध्यापक समर्पित होने चाहिए जो ट्रांसफर में न उलझकर अपनी सेवा गुणवत्ता से प्रदान करें।	शिक्षा विभाग
3.	प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से भी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं करने की नीति तैयार होनी चाहिए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	नगर निगम मण्डी के लिए रू0 15 करोड़ की राशि से विकास कार्य किए जाएं।	शहरी विकास विभाग
5.	शिवधाम प्रोजेक्ट के कार्य को पूर्ण किया जाए।	पर्यटन विभाग
6.	मण्डी विश्वविद्यालय के स्पोर्टस कॉम्पलैक्स के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भूमि शिक्षा विभाग के नाम की जाए।	शिक्षा/स्वास्थ्य विभाग
7.	मण्डी बाईपास सड़क को शीघ्र नाबार्ड से स्वीकृत करवाया जाए।	लोक निर्माण वि0
8.	बल्ह में बनने वाले एयरपोर्ट को नंदगढ़ नामक स्थान पर निर्मित करने बारे विचार किया जाए जिसके लिए एनएच के लगभग 7 कि0मी नजदीक 100 बीघा सरकारी तथा 200 बीघा निजी भूमि भी कम लागत पर अधिग्रहित की जा सकती है।	पर्यटन विभाग
9.	बस अडडा मण्डी को लोकल बस अडडे से 2 कि0मी0 आगे की भूमि पर आधुनिक रूप में भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण

10	मण्डी से जेल स्थानांतरित होनी है शीघ्र की जाए साथ ही पूर्ण बजट प्रावधान कर निर्माण कार्य तीव्रगति से आरम्भ/पूरा किया जाए।	पुलिस/ लोक निर्माण विभाग
11	मण्डी टाउन की डीपीआर को माननीय विधायक के साथ मिलकर/रिवाईज कर अन्तिम रूप प्रदान किया जाए।	शहरी विकास विभाग
12	मण्डी अस्पताल में ऐनेसथिसीया का डॉक्टर नियुक्त किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
13	मण्डी मातृ एवं शिशु अस्पताल में पूरे स्टाफ की नियुक्ति सुनिशचित की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
14	मण्डी टाउन, पार्किंग व अन्य निर्माण के कार्य एनजीटी के आदेशों के कारण रुका पड़ा है। इन आदेशों का सरलीकरण किया जाए या इन आदेशों को रदद करवाया जाए।	शहरी विकास विभाग
8. श्री ईन्द्र सिंह गॉंधी, बल्ह		
1.	विद्युत विभाग के मण्डलीय कार्यालय नेरचौक को खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	HPSEBLtd./ सामान्य प्रशासन
2.	आईटीआई रिवालसर को खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	पुलिस चौकी रिवालसर को थाना बनाने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग/ सामान्य प्रशासन
4.	पशु चिकित्सालय दुर्गापुर तथा पशु औषधालय स्योहली खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पशु पालन विभाग/ सामान्य प्रशासन
5.	सरकाघाट–हमीरपुर सड़क के अन्तर्गत कलखर–नेरचौक सड़क को चौड़ा (विस्तारीकरण) किया जाए।	लो0नि0 विभाग
6.	मण्डी–बैहना से नलसर वाया गागल सड़क का विस्तारीकरण कर इसे टू–लेन किया जाए।	लो0नि0 विभाग
7.	बल्ह वैली मिडीयम ईरीगेशन प्रोजेक्ट का सुधार कर गॉंव के अन्तिम छोर पर बैठे किसानों को भी पानी की सुविधा प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
8.	ग्राम पंचायत रत्ती से नेरचौक, नेरचौक से भंगरोटू, नेरचौक से डडौर तक गन्दे पानी की निकासी के लिए पक्की नालियों का निर्माण के साथ नेरचौक शहर के दोनो तरफ नालियों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर शेष कार्य को पूर्ण किया जाए।	शहरी/ग्रामीण/ पंचायती राज विकास विभाग
9.	सुकेती खडड का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10	रिवालसर–हरिद्वार बस सेवा शुरू की जाए।	परिवहन विभाग
11	रिवालसर से नैणा माता मन्दिर वाया गुदाहण तथा कुम्मी से नेरचौक मेडिकल कॉलेज वाया टांवा, कन्सा चौक के लिए बन्द की गई मुद्रिका बस सेवा को पुनः शुरू किया जाए।	परिवहन विभाग
12	प्रदेश के गरीब भूमिहीन परिवारों ने सरकारी 2–3 बिस्वा भूमि पर मकान बनाएं है इन्हे नियमित किया जाए।	वन / राजस्व विभाग/ उपायुक्त
13	मण्डी से रिवालसर वाया गागल मुद्रिका बस सेवा का संचालन किया जाए।	परिवहन विभाग
14	निर्वाचन क्षेत्र में बनी छोटी–छोटी सड़कों का विस्तार (extend) किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9. श्री दलीप ठाकुर, सरकाघाट		
1.	पॉलटेक्निक कॉलेज खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	पशु औषधालय खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पशु पालन विभाग/ सामान्य प्रशासन

3.	सरकाघाट बस अडडे निर्माण को बड़ी बहुमंजिला पार्किंग के रूप में डिजाईन कर बनाया जाए। साथ ही बलद्वाड़ा में भी बस अडडे का निर्माण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
4.	33 के.वी. सब-स्टेशन बलद्वाड़ा में लगना है इसे 33 के.वी. कलखर के साथ जोड़कर क्षेत्र में बिजली की समस्या का समाधान किया जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
5.	सरकाघाट बस डिपो में अतिरिक्त बसें चलाकर बसों की कमी को दूर किया जाए।	परिवहन विभाग
6.	त्रिफालघाट-भटेड़ा-चौकी-कशमैला-चैड़ीधार-मुरारी माता मन्दिर सड़क के बीच के 4 कि0मी0 कच्चे क्षेत्र को पक्का किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	नवाही-चमयाणु-कोट्लू-गोपालपुर-ठाणा, प्लासी-समैला-घोड़ी मतोली-त्रिफालघाट, सरकाघाट-रोपड़ी-रिशा सड़कों की मैटलिंग/ टारिंग का कार्य गुणवत्ता के साथ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8.	भांवला औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए।	उद्योग विभाग
9.	सरकाघाट में मेडिकल कॉलेज खोला जाए।	स्वास्थ्य विभाग
10	सरकाघाट में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए।	शिक्षा विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र में बन्द पड़ी छोटी-छोटी सड़कों को बजट उपलब्ध करवाकर प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग
	9. जिला चम्बा	
	1. श्री हंस राज, चुराह	
1.	चम्बा मेडिकल कॉलेज के दो एडमिन ब्लॉकों का निर्माण शीघ्र किया जाए ताकि केन्द्र से बजट प्राप्त हो सके और इसका संचालन आरम्भ हो सके।	स्वास्थ्य विभाग
2.	चुराह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएचसी कोहाल, बैरागढ़ तथा तीसा अस्पताल 100 बिस्तर खोलने/करने की जो अधिसूचनाएं रदद की गई हैं उन्हें बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	विकास खण्ड चुराह में खोलने की रदद अधिसूचना को बहाल किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग/ सामान्य प्रशासन
4.	बर्फबारी में बन्द हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए। साथ ही विभाग के अतिरिक्त (मशीनरी तथा मैनपॉवर कम होने के चलते) प्राईवेट लोगों को ही सड़क खोलने के टैण्डर प्रदान कर दिए जाएं।	लोक निर्माण विभाग
5.	विद्युत विभाग का डिवीजन तथा सब-डिवीजन तीसा में भौगोलिक स्थिति को देखेते हुए खोलने की रदद अधिसूचना को बहाल किया जाए।	HPSEBLtd./ सामान्य प्रशासन
6.	एनएच द्रमण से पांगी वाया जोत-चुराह की डी.पी.आर. शीघ्र स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	चम्बा जिला को हैलीपोर्ट की सुविधा तथा हैली टैक्सी की सेवा प्रदान की जाए।	पर्यटन विभाग
8.	कुगती, मणिमहेश यात्रा, गढ़ासरू महोदव, मैहलवार धार, साच पास इत्यादि क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
9.	डलहौजी क्षेत्र के सीमावर्ती ईलाका पधरी में पर्यटन के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा हटस बनाकर कब्जा किया गया है इस बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	पर्यटन / पुलिस विभाग
10	लगभग 600 के करीब एसपीओज़ (Special Police Officer) अपनी सेवाएं दुर्गम बर्फीले ईलाकों में प्रदान कर रहे हैं। इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए या उचित वेतन के साथ सारे लाभ प्रदान किए जाएं।	पुलिस विभाग
11	बनौड़ी से मन्सा सड़क पर अलवास से ऊपर की सड़क का निर्माण विभाग द्वारा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

12	निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों, मनरेगा या अन्य माध्यम से बनी 246 सड़कों की सुरक्षा/मैटलिंग/टारिंग का कार्य लोक निर्माण विभाग पूरा करे या ऐसे निर्देश दिए जाएं कि मनरेगा या अन्य माध्यम से इनकी सुरक्षा/मैटलिंग/टारिंग का कार्य पूर्ण किया जा सके।	लोक निर्माण विभाग
13	क्षेत्र के सभी स्कूलों में स्टाफ के लगभग सभी पद रिक्त चल रहे हैं इन रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए। या फिर अन्य माध्यम (मनरेगा/ विधायक निधि) से अध्यापकों/प्रवक्ताओं के पदों को भरने की अनुमति प्रदान की जाए।	शिक्षा विभाग
2. डॉ0 जनक राज, भरमौर		
1.	पीएचसी सुराल खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है इसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	सीएचसी भरमौर में एक ही एम्बुलैन्स है ऐसे दुर्गम/पहाड़ी/बर्फीले क्षेत्रों में एम्बुलैन्सों की संख्या (ड्राईवरों सहित) को बढ़ाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3.	निर्वाचन क्षेत्र के अधीन सभी सरकारी संस्थानों में कर्मठ, ईमानदार कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो केवल उसी क्षेत्र के लिए समर्पित रहकर अपनी सेवाएं प्रदान करे।	समस्त विभाग
4.	गैर जनजातीय क्षेत्र भरमौर में गददी समुदाय के लोग रहते हैं इन क्षेत्रों की 24 पंचायतों को TASP से बाहर कर केन्द्रीय योजना Modified Tribal Area Plan में सम्मिलित कर योजना का लाभ प्रदान किया जाए।	जनजातीय विकास विभाग
5.	पांगी घाटी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 10 मेगावॉट का प्रोजेक्ट लगाया जाए (5 मेगावॉट पांगी घाटी के एक छोर पर तथा दूसरा 5 मेगावॉट पांगी घाटी के दूसरे छोर पर)।	HPPCLtd.
6.	होली–उतराला सड़क की डीपीआर नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	पठानकोट–भरमौर सड़क डबल लेन के कार्य में एक लेन रावी नदी के दांई ओर तथा दूसरी लेन रावी नदी के बांई ओर निर्मित की जाए ताकि एक हिस्सा किसी कारण बर्बाद होने पर भी आवाजाही होती रहे।	लोक निर्माण विभाग
8.	निर्वाचन क्षेत्र के साथ–साथ पूरे प्रदेश में आवासीय शिक्षा प्रणाली को बढ़ाया जाए।	शिक्षा विभाग
9.	विद्युत विभाग में सभी श्रेणी के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए तथा पूरे वर्ष निर्बाध विद्युत आपूर्ति का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।	HPSEBLtd.
10	क्षेत्र में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
11	भरमौर तथा पांगी में एपीएमसी की या अन्य माध्यम से सब्जी मण्डी का निर्माण किया जाए।	कृषि विपणन बोर्ड
12	प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष दी /ली जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के स्थान पर हैल्थ कार्ड बनाकर, प्रीमियम देकर कैशलैस सुविधा प्रदान करने बारे विभाग विचार करे।	स्वास्थ्य विभाग
13	प्रदेश के कारागार/बंदीगृह/जेलों में रह रहे कैदियों का भी हिमकेयर कार्ड बनाकर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए।	पुलिस/ स्वास्थ्य विभाग
3. श्री नीरज नैयर, चम्बा		
1.	चम्बा मेडिकल कॉलेज के दो एडमिन ब्लॉकों का निर्माण शीघ्र किया जाए ताकि केन्द्र से बजट प्राप्त हो सके और इसका संचालन आरम्भ हो सके।	स्वास्थ्य विभाग
2.	मेडिकल कॉलेज चम्बा में गाईनियोकलाजिस्ट के 6–7 स्थायी पद स्वीकृत कर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग

3.	जिला चम्बा के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों को स्थायी तौर पर नियमित रूप से नियुक्ति करने के लिए कान्ट्रैक्ट के डॉक्टरों के समान उनके वेतन में बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि वह समर्पित भाव से वहीं पर अपनी सेवाएं प्रदान करे सके।	स्वास्थ्य विभाग
4.	एमसीआई के तहत मेडिकल कॉलेज चम्बा की अप्रूवल शीघ्र प्राप्त की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	मेडिकल कॉलेज में पानी की कमी की आ रही समस्या को हल करने के लिए योजना का निर्माण कार्य तुरन्त आरम्भ/पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	जंक्शन विद एनएच–154 ऐट ध्रमण, सिहुंता, चुवाड़ी, जोत, चम्बा, कोटी, तीसा, त्रैला, बैरागढ़, किलाड़ सड़क को केन्द्र से अविलम्ब स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7.	चम्बा शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए पुराने बस अडडे के स्थान पर मल्टीपर्पज भवन का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास/ परिवहन विभाग
8.	चम्बा टाउन के लिए रू0 480 करोड़ की डीपीआर को केन्द्र/ एडीबी/ अन्य माध्यम से 90:10 या 80:20 में स्वीकृत करवाकर विकास कार्य आरम्भ किए जाएं।	शहरी विकास विभाग
9.	उपायुक्त कार्यालय के पीछे की भूमि पर मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त
10	चम्बा इन्डोर स्टेडियम के लिए 2.5 करोड़ रू0 केन्द्र के पास से लोक निर्माण विभाग को प्रदान करवाए जाएं और निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	युवा खेल सेवाएं/ लोक निर्माण विभाग
11	हैलीपोर्ट के नीचे की तरफ की भूमि को सुरक्षित करने के लिए तथा अन्य 3 लैंड स्लाईड क्षेत्रों में भू–स्खलन मिटिगेशन की डीपीआर को स्वीकृत कर सुरक्षा कार्य आरम्भ/पूर्ण किया जाए।	उपायुक्त चम्बा
12	सुल्तानपुर–माई का बाग सीवरेज योजना के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाकर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
4. श्री डी. एस. ठाकुर, डलहौजी		
1.	पीएचसी भड़ेला व करवाल को खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है इसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
2.	बीडीओ कार्यालय बाथरी को खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है इसे बहाल किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	सलूणी के साथ लगता क्षेत्र भांदल से पधरी जोत लंगेरा तक खोल दिया है शेष 15 कि0मी0 की बन्द सड़क को प्राथमिकता के आधार पर खोला जाए। साथ ही लिंक सड़कें जो बर्फबारी से बन्द पड़ी हैं को भी खोला जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	सिवील अस्पताल 50 बिस्तर के कार्य को तीव्रगति से पूरा किया जाए।	स्वास्थ्य/ लोक निर्माण विभाग
5.	पधरी जोत में सलूणी तहसील के अन्तर्गत लगभग 17 हजार बीघा भूमि जम्मू कश्मीर में है इसे वापिस हिमाचल में लाया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त
6.	डलहौजी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
7.	डलहौजी में बस अडडे का निर्माण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
8.	नगर परिषद डलहौजी में चल रहे विकास कार्यों को तीव्रगति से पूरा किया जाए तथा आने वाले पर्यटकों को ठहरने के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ डलहौजी नगर परिषद	शहरी विकास/ पर्यटन विभाग

	को पर्यटन की दृष्टि से भी स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत विकसित किया जाए।	
9.	सीएच किहारा तथा सलूणी, क्षेत्र की पीएचसी व सीएचसी में डॉक्टरों, स्टाफ नर्स व अन्य तकनीकी स्टाफ के सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। साथ ही निकाली गई आउटसोर्स के आधार पर अपनी सेवाएं दे रही स्टाफ नर्सों को भी बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
10	सलूणी ब्लॉक के पटवार सर्कलों में पटवारी के रिक्त पदों को भरा जाए।	राजस्व विभाग
11	प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कलों में प्री–नसर्री की कक्षाएं आरम्भ की जाएं।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
12	नाबार्ड के पास स्वीकृति हेतु लम्बित बाथरी से सलूणी, नघेरा 2 लेन सड़क की डीपीआर को शीघ्र स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
13	लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों सलूणी तथा डलहौजी में ड्राईंग ब्रान्च में सभी रिक्त पदों को भरा जाए क्योंकि तभी विकास योजनाओं की कोई भी डीपीआर शीघ्र निर्मित हो सकती है।	लोक निर्माण विभाग
14	हाईडल प्रोजेक्ट भांदल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए तथा प्रस्तावित हाईडल प्रोजेक्ट सुंडला को स्वीकृत कर इसका भी निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सके।	HPPCLtd.
15	पर्यटन की दृष्टि से खजियार, डलहौजी और भलेई माता ऐतिहासिक मन्दिर को रोपवे के साथ जोड़ा जाए।	RTDC
16	जनसंख्या को ध्यान में रखकर आंगनबाड़ी केन्द्र, उप–तहसील, तहसील, पटवार सर्कल खोले जाएं।	राजस्व विभाग
17	कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक प्रोसेसिंग यूनिटों का निर्माण प्रदेश में किया जाए।	कृषि विपणन/ उद्यान विभाग
18	प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम लागत पर ऋण उपलब्ध करवाए जाएं।	सहकारिता विभाग
19	नशे पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।	पुलिस विभाग
20	सलूणी के साथ लगते पिछड़े क्षेत्रों की 43 पिछड़ी पंचायतों को सड़कों के साथ जोड़ा जाए।	लोक निर्माण विभाग
10.	**जिला शिमला**	
1. श्री बलबीर सिंह वर्मा, चौपाल		
1.	कुपवी, चौपाल तथा नेरवा अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें प्रदान की जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
2.	निर्वाचन क्षेत्र के लिए पीएचसी खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है उसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
3.	कुपवी अस्पताल निर्माण के शेष कार्य को रू0 1 करोड़ बजट उपलब्ध करवाकर पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4.	कुपवी/देहा में अग्निशमन केन्द्र खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है उसे बहाल किया जाए।	अग्निशमन विभाग/ सामान्य प्रशासन
5.	परिवहन विभाग डिपो नेरवा खुला है इसका पूरा संचालन तारोदवी के स्थान पर नेरवा से ही किया जाए। साथ ही वन/भूमि हस्तांतरण आपत्तियों का निपटारा कर भवन निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण किया जाए।	परिवहन/ वन विभाग
6.	जल शक्ति विभाग में 12–15 साल से बन रही लिफ्ट की योजनाओं को थोड़ा–थोड़ा आवश्यक बजट उपलब्ध करवाकर योजनाओं को पूर्ण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
7.	सैंज–देहा–चौपाल–नेरवा सड़क का एनएच के रूप में सुधार/ विस्तार /सुदृढ़िकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

8.	66 के.वी डोडापुल स्वीकृत है इसे अन्य स्थान पर स्थानांतरित न करके शीघ्र इसका निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPPTCLtd.
9.	पर्यटन की दृष्टि से सराहं मन्दिर से चूड़धार–नौहराधार के लिए रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
10	चौपाल मिनी सचिवालय निर्माण के लिए बजट का उचित प्रावधान किया जाए।	राजस्व विभाग
11	शिक्षा तथा विद्युत विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए।	शिक्षा/ विद्युत वि0
2. श्री कुलदीप सिंह राठौर, ठियोग		
1.	उद्यान विभाग के रू0 1134 करोड़ के प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट प्रदान की जाए।	उद्यान विभाग
2.	ठियोग में 5 सालों से रू0 150 करोड़ की लागत से बन रही पेयजल योजना के कार्य को तीव्रगति व गुणवत्ता के साथ पूरा कर क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या को हल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
3.	ठियोग क्षेत्र में बरसात के कारण खराब हुई सड़को की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए।	लोक निर्माण विभाग
4.	कोटगढ़, कुमारसैन तथा ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों तथा अन्य तकनीकी स्टाफ की पूर्ण नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5.	प्रदेश के राजस्व/आय में बढ़ोतरी के लिए पर्यटन तथा उद्यान विभागों में आधुनिक नीति अनुसार और नए स्त्रोतों का सृजन किया जाए।	पर्यटन/उद्यान विभाग
6.	नारकण्डा से हाटू रोपवे का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	RTDC
7.	सब–तहसील बड़ागांव तथा मतयाणा खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है उसे बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग/ सामान्य प्रशासन
8.	ठियोग अस्पताल को 200 बिस्तर करने की जो अधिसूचना रदद की गई है उसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
9.	ठियोग बाईपास का निर्माण कार्य तीव्रगति से पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3. श्री हरीश जनारथा, शिमला शहरी		
1.	शिमला शहरी में विद्यमान पार्किंगों में वाहन खड़े करने की क्षमता (Parking slots) में वृद्धि की जाए।	शहरी विकास/ नगर निगम शिमला
2.	शहरी क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करने में आ रही बाधा, एनजीटी के आदेशों को हटाया जाए या इनका सरलीकरण किया जाए।	वन/ शहरी विकास विभाग
3.	सभी विकास के प्रोजेक्ट/कार्यों में एफसीए/एफआरए लग रहा है इस प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाए नहीं तो कोई भी विकास कार्य करना सम्भव नहीं है।	वन विभाग
4.	शिमला शहर के विकास के लिए अलग से बजट का विशेष प्रावधान किया जाए।	शहरी विकास विभाग
5.	नगर निगम द्वारा टैक्स क्लेकशन के कार्य को पूरा किया जाए। जो विभाग/लोग कर नहीं दे रहे हैं उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जाए।	शहरी विकास/नगर निगम
6.	परिवहन विभाग द्वारा जो पार्किंग राजस्व नगर निगम को दिया जाना है उसे शीघ्र प्रदान किया जाए।	परिवहन/नगर निगम शिमला
7.	जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिमला शहर में केवल छोटी बसों या 20–25 सीट वाली ट्रेवलर का ही संचालन किया जाए।	परिवहन विभाग
8.	शिमला शहर के साथ–साथ जहां पर भी स्मार्ट सिटी से काम होना है, पूरी योजना/प्लान के साथ भविष्य को ध्यान में रखकर आधुनिक रूप से विकास के कार्य होने चाहिए।	शहरी विकास विभाग

9.	पेयजल की समस्या से शिमला शहर की जनता को निजात दिलाई जाए तथा पानी के स्टोरेज टैंकों का निर्माण वहां किया जाए जहां पर पानी पहुंचाना/जरूरत है।	शहरी विकास विभाग/ नगर निगम शिमला
10	नए एसटीपी प्लांटस बनाने के स्थान पर शिमला शहर में या इससे सटे पुराने एसटीपी प्लांटस का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार किया जाए।	शहरी विकास विभाग/ नगर निगम शिमला
11	शिमला शहर में विद्यमान केन्द्रीय विभागों/संस्थानों से भी पूरा टैक्स लिया जाए ताकि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।	शहरी विकास विभाग/ नगर निगम शिमला
12	शिमला शहर में विद्यमान केन्द्रीय विभागों जैसे रेलवे व अन्य संस्थानों के पास खाली पड़ी भूमि को राज्य सरकार विकास कार्यों (पार्किंग, शॉपिंग मॉल, सौन्दर्यकरण अन्य गतिविधियों) हेतु लीज़ पर/अधिग्रहण/अन्य माध्यम से लेकर शहर का विकास करे।	शहरी विकास विभाग
13	शिमला शहर के भीतर रिहैबिटेशन सेन्टरों का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास/ स्वास्थ्य विभाग
4. श्री नन्द लाल, रामपुर		
1.	विधायक प्राथमिकता में प्रस्तावित गत 5-6 वर्षो की डी.पी.आर. को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।	लो0नि0/ जल शक्ति विभाग
2.	ननखड़ी-रामपुर की जीवनरेखा, टिक्कर-खमाडी सड़क 52 कि0मी0 की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए। इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी पड़ती है जिससे हर साल यह सड़क खराब हो जाती है इसलिए हर वर्ष/दो वर्ष के अन्तराल पर इसकी मै0/टा0 का कार्य नियमित रूप से किया जाए। साथ ही इस सड़क की मुरम्मत की 2 डी.पी.आर. केन्द्र प्रस्तावित है को शीघ्र स्वीकृत कर मुरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ आरम्भ/पूरा किया जाए।	लो0नि0 विभाग
3.	लालसा-चिकसा सड़क जो बनकर तैयार है तथा पास भी हो चुकी है लेकिन वहां पर बस नहीं जा सकती। इस सड़क पर बस चलाने के लिए इसका सुधार किया जाए साथ ही मैटलिंग टारिंग के धीमी गति से हो रहे कार्य को तीव्रगति से गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।	लो0नि0 विभाग
4.	ब्रांदली खडड से सुंगरी सड़क की दयनीय स्थिति को (8 कि0मी0 विशेष स्थान) गुणवत्ता के साथ शीघ्र ठीक किया जाए।	लो0नि0 विभाग
5.	रामपुर में जाम की समस्या को हल करने के लिए बस स्टैण्ड से आगे की तरफ (across the river) विधायक प्राथमिकता में प्रस्तावित पुल का निर्माण किया जाए जिसके लिए प्रोजेक्ट से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।	लो0नि0 विभाग
6.	शानधार-श्रांईकोटी, चेवड़ी-नगालटी, चासनी-मढ़ोग के निर्माण/ मैटलिंग /टारिंग के कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।	लो0नि0 विभाग
7.	फांचा-नन्ती-टिक्कर सड़क, नोगली से ऊपर खनोरटू सड़क की डीपीआर तैयार कर शीघ्र इसे स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लो0नि0 विभाग
8.	उद्यान विभाग के अधीन बनने वाले सीए स्टोर झांगड़ का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूर्ण किया जाए। साथ ही एक नया सीए स्टोर रामपुर एरिया में एनएच के साथ बद्राश में निर्मित किया जाए।	उद्यान विभाग/ HPMC
9.	सराहन मन्दिर से बशनकंडा रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
10	राजकीय महाविद्यालय ननखड़ी के भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ की ज्यूरी कॉलेज की कक्षाएं अन्य स्थान पर अन्य भवन में चल रही हैं शीघ्र ही इस महाविद्यालय के लिए भूमि का प्रबन्ध कर भवन निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग

11	कोटला इंजिनीयरिंग कॉलेज के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कर सभी ट्रेड की कक्षाओं का सुचारू संचालन सुन्दरनगर के स्थान पर इसी कॉलेज से किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
12	रा०व०मा० पाठशाला टिप्पर–मझोली, शोली, कुंगलबाल्टी तथा खमाडी के निर्माणाधीन भवनों के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
13	स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग पांच साल से बन रहे ट्रामा सेन्टर खनेरी के लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
14	सब्जी मण्डी डकोलर, रामपुर का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	कृषि विपणन बोर्ड
15	निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन विभाग में ड्राईवरों तथा कन्डक्टरों की कमी को दूर कर बन्द पड़े 15–16 रूटों पर बस सेवा प्रारम्भ की जाए। साथ ही रामपुर से मुद्रिका बसों का भी संचालन किया जाए।	परिवहन विभाग
16	रामपुर में नदी पार के कुछ सीमित क्षेत्र जैसे ब्रौं तथा जगातखाना (कुल्लू क्षेत्र) को डी.एस.पी. रामपुर के अधीन किया जाए ताकि नशे की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नकेल कसी जा सके।	पुलिस विभाग
17	रामपुर में पार्किंग की समस्या को हल किया जाए।	उपायुक्त / लोक निर्माण विभाग
18	निर्वाचन क्षेत्रों की पीएचसीज़ में स्टाफ नर्सों की कमी को दूर किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
19	रामपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11. जिला लाहौल–स्पिती		
1. श्री रवि ठाकुर, लाहौल–स्पिती		
1.	लाहौल स्पिती की भौगोलिक एवं पर्यटकीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऐसे पेड़–पौधों को लगाया जाए जिससे आक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके और आने वाले पर्यटक रात को भी यहां ठहर सकें जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।	पर्यटन/ वन/ जनजातीय विकास विभाग
2.	अन्य राज्यों की सीमा से सटे लाहौल स्पिती के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत/सुदृढ़ किया जाए ताकि भारी बर्फबारी (6 माह/अधिकांश) में भी स्थानीय लोग कुल्लू, मनाली, बंजार, सोलन, धर्मशाला इत्यादि स्थानों पर माइग्रेट होने पर मजबूर न हों और घुसपैठिये यहां की भूमि पर कब्जा न कर पाएं।	जनजातीय विकास विभाग/ उपायुक्त
3.	लाहौल स्पिती में सिंचाई तथा पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए क्योंकि यहां पर कभी भी बर्फीली बाढ़, भारी वर्षा/बर्फबारी होती रहती है और अधिकतर बर्फबारी के कारण पानी की पाईपें हमेशा जाम रहती हैं।	जल शक्ति विभाग
4.	क्षेत्र में स्नो हारवेस्टिंग प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5.	उदयपुर, केलांग तथा काजा में सीवरेज की सुविधा प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
6.	केलांग में विशेषज्ञ डाक्टरों के सात में से छः पद रिक्त हैं इन्हें भरा जाए तथा काजा क्षेत्र के लोगों को अलसर, कैंसर, हेपाटाईटिस–बी हो रहा है इस बारे विभागीय टीम का प्रबन्ध कर निरीक्षण के लिए भेजा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7.	लाहौल स्पिती के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए केलांग में आईसीएमआर के अधीन NIRATH नाम का संस्थान स्वीकृत किया गया है इसे जनहित में चालू (functional) किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग

८.	निर्वाचन क्षेत्र के स्कूलों में विज्ञान विषय (फिजीक्स, कैमिस्ट्री, मेडिकल) के अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	शिक्षा विभाग
९.	पॉलटेक्निक कॉलेज उदयपुर में स्वीकृत है इसकी कक्षाएं सुन्दरनगर में चल रही हैं, इन कक्षाओं का सुचारू संचालन उदयपुर से ही सुनिश्चित किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
10	लाहौल स्पिति को (दारचा पंचायत में 500–700 बीघा भूमि पर) पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
11	क्षेत्र में पशु चिकित्सकों/सहायकों के सभी रिक्त पदों को भरा जाए।	पशु पालन विभाग
12	चार रोपवे निर्माण की प्रस्तावनाओं को पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य शुरू किया जाए।	RTDC
13	पर्यटन की दृष्टि से काजा, क्वांग, सिस्सु, जिस्पा में बनने वाले आईस स्केटिंग रिंक, स्की लिफट, आईस हॉकी इत्यादि के कार्यो को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	पर्यटन विभाग/ उपायुक्त लाहौल–स्पिती
14	लाहौल स्पिती में कम उंचाई वाले पेड़ों (कश्मीर विलो) को लगाया जाए और क्षेत्र में लगे (चांगमा आदि किस्म के) पेड़ों की नस्ल में सुधार किया जाए।	वन विभाग
15	उदयपुर–तिंदी सड़क, सुन्दोह–ग्राम्फू–काजा (SKTT & SKG) सड़क की एफसीए /एफआरए के मामलों को शीघ्र निपटाकर इन सड़कों के मैटलिंग/टारिंग के कार्य को शीघ्र गुणवत्ता के साथ आरम्भ/पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
16	जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ लगते सिंकुला पास तथा सरचु क्षेत्र की डिमार्केशन करवाई जाए।	राजस्व विभाग
17	लगभग 600 के करीब एसपीओज़ (Special Police Officer) अपनी सेवाएं दुर्गम बर्फीले ईलाकों में प्रदान कर रहे हैं। इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए या उचित वेतन के साथ सारे लाभ प्रदान किए जाएं।	पुलिस विभाग
18	नवीकरणीय ऊर्जा (renewal energy) के क्षेत्र में लाहौल स्पिती में बड़ा प्लांट स्थापित किया जाए।	ऊर्जा/हिम ऊर्जा विभाग/ HPPCLtd.
19	क्षेत्र की जनता को बिजली की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए 4 मेगावॉट के प्रोजेक्ट कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	HPPCLtd./ हिम ऊर्जा विभाग
20	रौंगटौंग प्रोजेक्ट तथा ट्रांशमिशन लाईन में सुधार किया जाए।	HPPCLtd./ HPTCLtd.
21	मुदभावा सड़क तथा लियो बाई पास सड़क का निर्माण/सुधार/ विस्तार/सुदृढ़ीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
22	परिवहन विभाग की पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें प्रदान की जाएं।	परिवहन विभाग
23	क्षेत्र में डिजल पम्म लगाया जाए तथा शैड बनाया जाए।	परिवहन विभाग
24	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा Budhist Institute University को इस क्षेत्र में स्थापित किया जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग

दो दिवसीय बैठकों के अन्त में मुख्य मन्त्री महोदय ने कहा कि इन तीन दिवसीय बैठकों में 68 विधायकों में से 65 माननीय विधायकों ने भाग लिया । बैठकों में प्रदेश महत्व के विभिन्न मुद्दे माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए हैं । कुछ मुद्दों पर बैठकों में ही निर्णय लिए गए हैं । अन्य मुद्दों पर विभाग तुरन्त कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से सरकार को अवगत करवाएंगे। माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास किया जाएगा तथा विकास में रही त्रुटियों को दूर किया जाएगा।

बैठकों के समापन पर मुख्य सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश ने माननीय मुख्य मन्त्री, मन्त्रीगण, विधायकों, समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी उपायुक्तों व उपस्थित अन्य अधिकारियों का तीन दिवसीय बैठकों में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया तथा स्पष्ट किया कि तीन दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी विभागों द्वारा तुरन्त एवं पूर्णतः से पालन किया जाएगा । प्रदेश के चहूंमुखी तथा समाज के सभी वर्गों के त्वरित व सन्तुलित विकास के लिए सम्पूर्ण प्रशासन सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा । सभी सम्बन्धित विभाग बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से सम्बन्धित माननीय विधायकों तथा योजना विभाग मुख्यालय को समयबद्ध सीमा में अवगत करेंगे। तीन दिवसीय बैठकें धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुईं।

तीन दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश

क्र. सं.	माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के निर्देश	सम्बन्धित विभाग
1.	प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों तथा पानी के पक्के स्त्रोतों (Permanent source of water) को ध्यान में रखते हुए ही सिंचाई की योजनाओं को विधायक प्राथमिकता में डालें ताकि सफलतम सिंचाई योजना (Assured Irrigation) की सुविधा जनता को प्रदान की जा सके।	समस्त माननीय विधायक/ जल शक्ति विभाग
2.	विधायक प्राथमिकता योजनाओं के निर्धारित प्रपत्र पर सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई तथा ग्रामीण पेयजल/ मल निकासी योजनाओं के शीर्ष लम्बे समय से चल रहे हैं। आज की इन बैठकों से ही सभी माननीय प्रपत्र में इंगित शीर्षों के अतिरिक्त नाबार्ड के तहत आर.आई.डी.एफ. कार्यक्रम की Eligible Activity की योजनाओं को भी प्रदान कर सकते हैं, जिस पर सरकार के दिशा–निर्देशोंनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।	योजना विभाग
3.	शिक्षा, चिकित्सा विज्ञान तथा पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर योगदान प्रदान कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है जिसके लिए किसी एक जिला को पर्यटन राजधानी (Tourism Capital) बनाना है।	शिक्षा/स्वास्थ्य/ पर्यटन विभाग
4.	राज्य को आर्थिक तंगी से बाहर निकालने में सभी विभाग प्रयास करे तथा अनचाहे खर्चों पर रोक लगाए।	समस्त विभाग/ उपायुक्त
5.	Electric Vehicle Programme को विभाग तीव्रगति से बढ़ाए।	परिवहन विभाग
6.	सभी विभागीय अधिकारी विधायक प्राथमिकता योजनाओं के साथ–साथ अन्य प्रकार की सभी योजनाओं को निर्धारित समयावधि (Targeted / Fixed Time Period) में ही पूरा करे।	समस्त विभाग/ उपायुक्त
7.	नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा नगर पंचायत/नगर परिषद/ नगर निगम की परिधी क्षेत्र की सीमाओं को 500 मीटर, 200 मीटर या 100 मीटर तक निर्धारित किया जाए तथा नगर पंचायत/नगर परिषद/ नगर निगम के साथ लगती पंचायतों की खाली भूमि पर लोगों को किसी भी प्रकार का कर बोझ न पड़े इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही जिस क्षेत्र को नगर पंचायत/नगर परिषद/ नगर निगम के अधीन किया गया है और जहां पर निकट 40–50 वर्षों तक विकास की सम्भावना नहीं है उनके घरों पर भी कर न लगाया जाए।	शहरी विकास विभाग

8.	गगरेट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में नगर पंचायत के अन्तर्गत सेना की खाली पड़ी भूमि को अधिग्रहित करने बारे जिलाधीश तीव्रगति से कार्य करे।	उपायुक्त ऊना
9.	सभी विभाग टैण्डर की प्रक्रिया को 7 दिन तथा कार्य आबंटन को 20 दिन के भीतर करने के आदेशों का गम्भीरता से पालन करे।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/ समस्त विभाग
10.	लोक निर्माण विभाग में Architecture (structural design) and Electrical की टैण्डर प्रक्रिया अलग-अलग न कर एक साथ ऑनलाईन की जाए। साथ ही ठेकेदारों को empanel किया जाए ताकि यदि एक काम न करे तो दूसरे ठेकेदार को उसी मूल्य पर काम दिया जा सके।	लोक निर्माण विभाग/ सम्बन्धित विभाग
11.	किसी भी योजना / परियोजना की AA & ES को Time bound किया जाए।	लोक निर्माण विभाग/ सम्बन्धित विभाग
12.	लोक निर्माण विभाग में Architecture Wing प्रदेश की भौगोलिक तथा मौसमीय परिस्थितियों (ठण्डे तथा गर्म इलाकों) को ध्यान में रखकर भवन निर्माण की योजना बनाए। कमरों के नक्शों में परिवर्तन करने के साथ-साथ भवनों के नक्शों को तैयार करते समय सोलर छत डिजाईन को प्रमुखता से अपनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग/ सम्बन्धित विभाग
13.	लोक निर्माण विभाग में सड़कों के निर्माण में पीसी तथा बीसी के उपयोग की महत्वता तथा वैकल्पता की रूपरेखा 14-15 फरवरी, 2023 की बैठक में प्रस्तुत करे।	लोक निर्माण विभाग
14.	जल शक्ति विभाग प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण ईलाकों में 24 घंटे पानी की योजनाओं का निर्माण कर आपूर्ति सुनिश्चित करे तथा per litre consumption में भी बढ़ोतरी करे।	जल शक्ति विभाग
15.	टाऊन हाल सुजानपुर का निर्माण हेतु चौगान के बाहर की भूमि हस्तांतरण का मामला राजस्व विभाग अधिसूचना/ एक्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए।	उपायुक्त हमीरपुर
16.	जल शक्ति विभाग के डिवीजन में कुछ पंचायतें बड़सर तथा भोरंज डिवीजन में पड़ती हैं इन्हें हमीरपुर डिवीजन में शामिल करने बारे विभाग कार्यवाही करे।	जल शक्ति विभाग
17.	पुराना बस अडडा हमीरपुर के दांई ओर, बांई ओर तथा पीछे की तरफ भूमि अधिग्रहण करने बारे विभाग तथा उपायुक्त मिलकर 15 फरवरी तक मामला प्रस्तुत करे, क्योंकि इस बजट में इसका निर्माण कार्य करना ही है।	बस अडडा प्राधिकरण/ उपायुक्त हमीरपुर
18.	बस अडडा मैहरे/बड़सर के निर्माण सम्बन्धी भूमि की माननीय विधायक द्वारा बताई गई तीनों साईटों (प्राईवेट ट्रस्ट भूमि, फॉरेस्ट कॉरपोरेशन भूमि तथा वर्तमान प्रस्तावित भूमि) का परिवहन विभाग के साथ मिलकर, अध्ययन कर निर्माण सम्बन्धी मामला प्रस्तुत करे।	बस अडडा प्राधिकरण/ राजस्व विभाग / उपायुक्त हमीरपुर
19.	प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में बैठने के लिए बैंच, शौचालय की व्यवस्था (Male and Female) अनिवार्य की जाए। साथ ही कितने मुरम्मत के लिए भवन, नए बनने वाले भवन इत्यादि का ब्यौरा 15 फरवरी, 2023 तक पूर्ण सुधारात्मक नीति के साथ प्रस्तुत करें।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
20.	प्रदेश में किसी भी शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कार्य केवल लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाएगा।	लो0 नि0/ शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा /तकनीकी शिक्षा/ सम्बन्धित विभाग

21.	मुख्यमंत्री सहारा योजना के अन्तर्गत मरीजों के बैंक खातों को लिंक किया जाए तथा ऑनलाईन माध्यम से पैसे सीधे उनके खाते में 5 तारीख से पहले प्रदान करने के लिए आई.टी. विभाग के साथ मिलकर सभी उपायुक्त कार्य करे।	स्वास्थ्य /आई.टी. विभाग/ समस्त उपायुक्त
22.	सभी विभागों जिनके विकास कार्य एनजीटी के कारण रूके हुए हैं उनकी सूची/ आदेश सहित मुख्यमंत्री कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र भेजी जाएं।	समस्त विभाग/ सामान्य प्रशासन
23.	मनाली आईस स्केटिंग रिंक तथा बाई पास सड़क के कार्य को expedite किया जाए।	लोक निर्माण/ वन विभाग
24.	पूरे प्रदेश में पर्यटन तथा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए छोटे स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन निर्माण (Eco friendly) में कुछ नियमों एवं शर्तों का प्लान तैयार किया जाए।	पंचायती राज/ पर्यटन विभाग
25.	कन्सलटैन्सी टैण्डर समयावधि को कम किया जाए।	लोक निर्माण वि0
26.	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सुरंग निर्माण के सारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करे।	लोक निर्माण विभाग
27.	बगासराहन से बठाड़ के लिए सुरंग का निर्माण करने बारे विभाग कार्य करे।	लोक निर्माण वि0
28.	स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने तथा नए स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने के स्थान पर पुराने संस्थानों को सुदृढ़/मजबूत करने बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	स्वास्थ्य विभाग
29.	पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के लिए हाब्बन से सुरंग निर्माण करने बारे विभाग माननीय विधायिका से मिलकर कार्यवाही करे।	लोक निर्माण विभाग
30.	मेडिकल कॉलेज नाहन के निर्माण में अनुमति के अतिरिक्त आ रहे वृक्षों को शीघ्र कटवाकर कार्य चालू किया जाए।	वन / स्वास्थ्य विभाग
31.	बाहरी राज्यों से सटे जिलों में माईनिंग को रोकने के लिए सभी पुलिस अधीक्षक विशेष ध्यान दे।	पुलिस विभाग/ सम्बन्धित उपायुक्त
32.	नाहन नगर परिषद में पार्किंग का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास विभाग
33.	भविष्य में बनने वाली पेयजल योजनाओं की डी.पी.आर. में नवीनतम तकनीक, फिल्टर तथा यू.वी. इत्यादि का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए जिसके लिए भारत सरकार की नई तकनीक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नवीनतम तकनीक का अध्ययन कर नीति तैयार की जाए।	जल शक्ति विभाग
34.	श्री रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र में नौहराधार के ऊपर के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
35.	सभी यूजर ऐजेन्सी तथा डीएफओ उपायुक्त के साथ मिलकर वन आपत्तियों का निपटान निर्धारित Time bound अवधि में पूरा करे और एफसीए से सम्बन्धित आपत्तियों का निपटान 3 दिन के भीतर यूजर ऐजैन्सी द्वारा किया जाए।	समस्त उपायुक्त / समस्त विभाग
36.	रेणुका डैम प्रोजेक्ट के बनने से मुख्य सड़क संगड़ाह को बन्द कर किसी अन्य स्थान से बनाया जाना है जिससे 14 कि0मी0 की दूरी बढ़ रही है। इसके स्थान पर यहां पर एक सुरंग का निर्माण करने बारे लोक निर्माण विभाग उचित कार्यवाही करे।	लोक निर्माण विभाग
37.	पूरे प्रदेश में भूमि की रजिस्ट्री ऑनलाईन घर बैठे करने तथा प्रदेश के भीतर एक स्थान से ही किसी भी जिला में रजिस्ट्री करने की सुवधिा जनता को प्रदान करने के लिए विभाग राष्ट्रीय स्तर पर चल रही e-registry सुविधा का पायलट आधार पर प्रयोग कर इसे कार्यान्वित करने बारे कार्यवाही करे।	राजस्व विभाग

38.	प्रदेश के सभी डीएफओ तथा यूजर एजैन्सी को एफसीए तथा एफआरए के मामलों में उपायुक्तों के अधीन जवावदेह किया जाए।	वन विभाग/ समस्त उपायुक्त/ समस्त विभाग/ सामान्य प्रशासन
39.	प्रदेश में जिस किसी विभाग में कन्स्ट्रक्शन डिवीजन है वह योजना को निर्धारित समयावधि (Targeted / Fixed Time Period) में पूरा करेगा। साथ ही ठेकेदारों को भी एम्पैनल किया जाए ताकि यदि एक काम न करे या बीच में छोड़ दे तो उसे दण्ड के रूप में जुर्माना लगाकर अन्य ठेकेदार को कार्य प्रदान किया जाए।	लोक निर्माण/ हिमुडा/ समस्त सम्बन्धित विभाग
40.	लगभग 15 साल पहले की योजना मझयार, कलूड, अमलैहड़ जिससे निरन्तर निर्बाध सिंचाई की सुविधा मिलनी थी अभी तक क्यों नहीं आरम्भ हुई की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	जल शक्ति विभाग
41.	सिवील अस्पताल जयसिंहपुर में लिफट, ट्रांसफार्मर, पानी इत्यादि की मूलभूत सुविधाओं का सुचारू संचालन किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
42.	एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ के कार्यालयों/आवासीय भवनों का निर्माण एक ही स्थान पर करने के लिए प्रशासनिक सचिव रूपरेखा तैयार करे।	राजस्व/ग्रामीण विकास विभाग
43.	सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई, परकोलेशन वैल, अन्य जनहित स्कीमों इत्यादि को ध्यान में रखकर इसके साथ लगते लगभग 1–2 कि0मी0 क्षेत्र में खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए और अवैध खनन पूरी तरह से रोका जाए।	उद्योग/ जल शक्ति विभाग
44.	जल शक्ति विभाग में योजनाओं को अवैध खनन से नुकसान करने वालों के विरूद्ध एफआईआर करने का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
45.	प्रदेश के पुराने शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़िकरण हेतु सम्बन्धित विभाग कार्यवाही करें।	प्रारम्भिक शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा/ शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/ सम्बन्धित विभाग
46.	जयसिंपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में राजीव डे बोर्डिंग स्कूल तथा कलस्टर विद्यालय खोलने बारे उपायुक्त कार्यवाही करे।	उपायुक्त कांगड़ा/ शिक्षा विभाग
47.	धर्मशाला से नडडी होते हुए सतोवरी–बरनेट–घेरा सड़क को पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
48.	शाहपुर के बोह क्षेत्र में लोगों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।	उपायुक्त कांगड़ा
49.	निर्वाचन क्षेत्र शाहपुर के लिए बल्ह–नडडी–करेरी–खड़ीबोही रोपवे निर्माण का मामला पर्वतमाला में प्रस्तावित किया जाए।	RTDC
50.	मांझी से धर्मकोट तथा ट्यूलिप गार्डन से चटकर रोपवे का निमार्ण पर्वतमाला में किया जाए।	RTDC
51.	पीएमजीएसवाई के मानदण्डों के अनुसार प्रदेश में बनने वाली सड़कों/लिंक सड़कों (नाबार्ड/अन्य माध्यम) का निर्माण/मैटलिंग / टारिंग की जाए।	लोक निर्माण विभाग
52.	बीबीएनडीए के अधीन क्षेत्र को विकसित करने के लिए इसे गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाए।	शहरी विकास/ उद्योग विभाग
53.	नालागढ़–भरतपुर, कालाअम्ब–पौंटा, नालागढ़–बघेरी–खातीवाल–गड़ामौड़ा, शिमला–मटौर सड़कों को 4 लेन बनाने के मामले में तीव्रता के साथ कार्य किया जाए और साथ ही सोलन–परवाणु 4 लेन सड़क की रिअलाईनमेंट की जाए।	लोक निर्माण विभाग
54.	विभाग भविष्य को ध्यान में रखते हुए 25–50 सालों के लिए प्लान बनाकर पाईपों के डाऐ की क्षमता को बढ़ाए।	जल शक्ति विभाग

55.	विभाग सड़कों पर पड़ी पाईपों को एक महीने के भीतर स्टोर में पहुंचाए और विभाग ठेकेदारों के माध्यम से नलों में उपयोग लाईनों को भूमिगत करे।	जल शक्ति विभाग
56.	कसौली के कैन्टोनमेंट एरिया में 100 से अधिक वर्षों से रह रहे लोगों की सभी समस्याओं (भूमि खरीद, मकान मुरम्मत, पक्के रास्ते इत्यादि) को हल करने का मामला प्रस्तुत करे।	उपायुक्त सोलन
57.	नाहन सड़क से आगे जौडजी से मल्ला सड़क पिंजौर निकलती है इसे सीआरएफ के माध्यम से 5 मीटर चौड़ाई का बनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
58.	सुबाथु कॉलेज को सरकार ने अपने अधीन लिया है इसके स्टाफ की समस्या को हल करने के साथ–साथ युजीसी के दिशा–निर्देशों को भी जांचा जाए।	शिक्षा विभाग
59.	ज्योरिपतन–स्वारघाट रोपवे का निर्माण पर्वतमाला में प्रस्तावित किया जाए।	RTDC
60.	माता नैनादेवी जी तथा बाबा बालक नाथ मन्दिर के बीच की सड़क दूरी को कम करने के लिए गोविन्द सागर झील पर केवल फैरी रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
61.	घुमारवीं निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान कम्बाईन्ड ऑफिस भवन निर्मित किया गया है जिसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए इस भवन को अन्य गतिविधियों पार्किंग, हॉल, कॉन्फ्रेन्स हॉल, आवासीय इत्यादि के लिए पायलट आधार पर चालू किया जाए ताकि सकारात्मक परिणाम आने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सके।	शहरी विकास विभाग/ उपायुक्त बिलासपुर
62.	औहर में टूरिस्ट कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि पर्यटन विभाग को प्रदान की जाए।	राजस्व/कृषि/पर्यटन विभाग
63.	प्रदेश में भूमि अधिग्रहण करने की समयावधि को कम किया जाए।	राजस्व विभाग
64.	निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर छोटे–छोटे कस्बों में लो वोल्टेज की समस्या, सड़क के साथ दुकानों तथा साथ लगते एरिया में बिजली की तारों के स्थान पर ओवरहैड केबल डालने के लिए डीपीआर का निर्माण किया जाए।	HPSEBLtd.
65.	पुलिस चौकी एम्स बिलासपुर को पुनः अधिसूचित किया जाए।	पुलिस विभाग
66.	नैनादेवी जी शक्तिपीठ को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए ट्रस्ट की ओर से कुछ नए कार्य किए जा रहे थे जैसे लिफ्ट लगाना, गोविन्द सागर झील की तरफ ग्लास पुल, सैल्फी प्वाईंट इत्यादि जो बन्द पड़े हैं इन्हें चालू किया जाए।	उपायुक्त बिलासपुर/ पर्यटन विभाग
67.	करसोग में Soil Testing Lab चलाने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के अन्तर्गत मामला चलाया जाए।	कृषि विभाग/ Soil Conservation
68.	1952 की अस्थाई पुलिस चौकी डैहर को स्थायी किया जाए।	पुलिस विभाग
69.	सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र में सलापड़ से तत्तापानी के रूट पर तथा सुन्दरनगर नहर में जैटीज़ चलाई जाएं।	पर्यटन विभाग/ HPPCLtd.
70.	सुन्दरगर के सुकेत में झील के किनारे कैफे चल रहा है जहां पर दो कमरे भी हैं। इस कैफे के विस्तारीकरण के लिए Convention Hall के निर्माण कार्य को किया जाए।	पर्यटन विभाग
71.	पंडोह, सलापड़ तथा सुन्दरनगर में बीबीएमबी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में अध्यापकों के पूरे पदों को सुचारू किया जाए।	शिक्षा विभाग
72.	किसी भी वर्तमान/ पूर्व माननीय सांसद, मन्त्री / विधायक व अन्य के शिलान्यास/पटि्टकाएं यदि तोड़ी गई हैं उन्हें सम्बन्धित विभाग पुनः उसी स्थान पर स्थापित करे और पुलिस विभाग ऐसे दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।	पुलिस/ समस्त विभाग/ समस्त उपायुक्त

73.	नाचन विधान सभा क्षेत्र में बरसात में बहे हुए 6 पुलों (5 वन विभाग+ 1 पंचायत द्वारा निर्मित) को पुनः रिस्टोर किया जाए।	वन/पंचायती राज / लोक निर्माण/राजस्व विभाग/ उपायुक्त मण्डी
74.	द्रंग विधान सभा के अन्तर्गत गुम्मा एनएच सब-डिवीजन में बेकार पड़े बुलडोजर तथा स्नोकटर लोक निर्माण विभाग के डिवीजन नम्बर-1 को प्रदान किया जाए।	लोक निर्माण वि०
75.	पुलिस चौकी लड़भड़ोल को थाना बनाने की रदद अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग
76.	रोगी कल्याण समितियों में प्रधान तथा बीडीओ को भी शामिल किया जाए तथा मनरेगा के तहत वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, कम्पयूटर ऑपरेटर 120 दिन हेतु पंचायत घरों, अस्पतालों अन्य सरकारी कार्यालयों में नियुक्त करने बारे विभाग प्रस्ताव प्रस्तुत करे। साथ ही बीडीओ तय करे कि मनरेगा में लगे लोगों को 120 दिन का काम सुनिश्चित करें।	स्वास्थ्य/ ग्रामीण विकास विभाग
77.	अटल आदर्श विद्यालय के अधूरे कार्य को पूर्ण कर कलस्टर विद्यालय/डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में इसका सुचारू संचालन किया जाए।	शिक्षा विभाग
78.	प्रदेश के भीतर चलाई जा रही सभी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर करवाने का कार्य सिर्फ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ही करेगा।	शिक्षा विभाग
79.	मण्डी विश्वविद्यालय के स्पोर्टस कॉम्पलैक्स के लिए स्वास्थ्य विभाग एक सप्ताह के भीतर आवश्यक भूमि को शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित करे।	शिक्षा/स्वास्थ्य विभाग / उपायुक्त मण्डी
80.	बल्ह में बनने वाले एयरपोर्ट को नंदगढ़ नामक स्थान पर निर्मित करने बारे विभाग निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।	पर्यटन विभाग
81.	बस अडडा मण्डी को लोकल बस अडडे से 2 कि0मी0 आगे की भूमि पर निर्माण करने बारे विभाग कार्यवाही करे।	बस अडडा प्राधिकरण
82.	प्रत्येक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष में ही किसी योजना की अनुमानित लागत में कई गुना की वृद्धि हो जाती है जोकि ठीक नहीं है, इसलिए लोक निर्माण विभाग रू0 5 करोड़ से ऊपर की सभी योजनाओं का इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड का एस्टीमेट ऑडिट करवाए साथ ही जिम्मेदारी भी निर्धारित करे।	लोक निर्माण विभाग
83.	उच्च न्यायालय में लम्बित अरबीट्रेशन के सभी मामलों को वापिस (withdraw) लिया जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/ समस्त सम्बन्धित विभाग
84.	भविष्य में बनने वाली सभी योजनाओं में अरबीट्रेशन क्लाज को समाप्त करने की सूचना टैण्डर में ही इंगित की जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग
85.	एनजीटी के कारण लम्बित मामलों को निपटाने के कार्य में तेजी लाई जाए।	मुख्य सचिव/ सामान्य प्रशासन
86.	पुलिस चौकी रिवालसर को थाना बनाने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग
87.	सरकाघाट-हमीरपुर सड़क के अन्तर्गत कलखर-नेरचौक सड़क को चौड़ा (विस्तारीकरण) करने की डीपीआर को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	लो0नि0 विभाग
88.	साच पास के ऊपर मैडोज (Meadows) के क्षेत्र को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने (रोपवे, ट्रेल इत्यादि) पर विभाग कार्य करे।	पर्यटन विभाग/ RTDC
89.	चम्बा जिला के जोत को जोड़ने वाली सड़क के कार्य (निर्माण/ प्रोटेक्शन वॉल/मैटलिंग/टारिंग इत्यादि) को पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

90.	चम्बा जिला के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जिला में लगे पॉवर प्रोजेक्टों / सीएसआर/सीआईआर के माध्यम से अतिरिक्त एम्बलैन्सों का ड्राईवरों सहित प्रबन्ध करवाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
91.	होली–उतराला सड़क को सुरंग के साथ एनएच घोषित करवाकर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
92.	प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष दी /ली जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) के स्थान पर हैल्थ कार्ड बनाकर, प्रीमियम देकर कैशलैस सुविधा प्रदान करने बारे विभाग विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे।	स्वास्थ्य विभाग
93.	प्रदेश के कारागार/बंदीगृह/जेलों में रह रहे कैदियों का भी हिमकेयर कार्ड बनाकर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान कर दी जाए।	पुलिस/ स्वास्थ्य विभाग
94.	मेडिकल कॉलेज चम्बा के लिए पानी की स्कीम निर्माण के कार्य को एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
95.	चम्बा शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए पुराने बस अडडे के स्थान पर मल्टीपर्पज भवन का निर्माण करने बारे शहरी विकास विभाग कार्यवाही करे।	शहरी विकास
96.	रोपवे विभाग केवल रोपवे से सम्बन्धित का ही निर्माण करे न कि किसी अन्य का। स्टेडियम/सुरंग व अन्य निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग ही करेगा।	RTDC/लोक निर्माण विभाग
97.	चम्बा हैलीपोर्ट के नीचे की तरफ की भूमि को सुरक्षित करने के मामले में उपायुक्त कार्यवाही करे।	उपायुक्त चम्बा
98.	कुपवी/देहा में अग्निशमन केन्द्र को बहाल किया जाए।	अग्निशमन विभाग
99.	छैला–यशवन्तगनर–राजगढ/कुमारहटटी सड़क को एनएच किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
100.	पर्यटन की दृष्टि से सराहं मन्दिर से चूड़धार–नौहराधार के लिए रोपवे का निर्माण किया जाए और पर्वतमाला के तहत प्रेषित किया जाए।	RTDC
101.	उद्यान विभाग के रू0 1134 करोड़ के प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	उद्यान विभाग
102.	नारकण्डा से हाटू रोपवे का निर्माण पर्वतमाला में किया जाए।	RTDC
103.	पहाड़ी क्षेत्रों (सेब बैल्ट, सीमेन्ट फैक्टरी बैल्ट) की सड़कों की मैटलिंग/टारिंग करने (मोटाई–30 एमएम, 40 एमएम इत्यादि) के नियमों में बदलाव किया जाए ताकि प्रदेश की सड़कों की कम से कम 5–6 साल तक मुरम्मत न करनी पड़े।	लोक निर्माण विभाग
104.	प्रदेश के जिन सरकारी भवनों पर स्टे नहीं है उन सब मामलों को न्यायालयों से वापिस (withdraw) लाया जाए।	लोक निर्माण/जल शक्ति/ समस्त सम्बन्धित विभाग
105.	शिमला शहरी में लोकल रूटस पर 50 छोटी गाड़ियां 20–30 सीट वाली चलाई जाएं।	परिवहन विभाग
106.	शिमला शहर के सर्कुलर सड़कों को चौड़ा करने के लिए एक ही बार में भूमि अधिग्रहित की जाए।	शहरी विकास विभाग/नगर निगम
107.	नगर निगम में मर्ज एरिया को सीवरेज की सुविधा प्रदान करने के लिए एसटीपी निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया में भूमि का शीघ्र अधिग्रहण कर निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण किये जाएं।	शहरी विकास विभाग
108.	विधायक प्राथमिकता में प्रस्तावित गत 5–6 वर्षों की डी.पी.आर. को विभाग मुख्य अभियन्ता तीव्रगति से प्राथमिकता के आधार पर तैयार करें।	लो0नि0/ जल शक्ति विभाग
109.	रामपुर सीए स्टोर जांगड़ के निर्माण हेतु भूमि एचपीएमसी के नाम की जाए और एकसाथ ही टैण्डर प्रक्रिया भी शुरू कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूर्ण किया जाए। साथ ही ISRO and DRDO की नवीनतम तकनीक का उपयोग करने का विस्तृत अध्ययन भी किया जाए।	उद्यान विभाग

110.	प्रदेश में निर्मित होने वाले सेब के सिरके (Apple Cider Vinegar) की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी की जाए साथ ही राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार/प्रसार (Marketing) किया जाए।	उद्यान विभाग/ कृषि विपणन बोर्ड
111.	सराहन मन्दिर से बशनकंडा तथा खड़ा पत्थर से गिरी रोपवे का निर्माण पर्वतमाला में किया जाए।	RTDC
112.	रामपुर में नदी पार के कुछ सीमित क्षेत्र जैसे ब्रौं तथा जगातखाना (कुल्लू क्षेत्र) को डी.एस.पी. रामपुर के अधीन किया जाए साथ ही प्रदेश में ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के मामलों में भी इसी उदाहरण/नीति को अपनाकर कानूनी शक्तियां हस्तांतरित की जाएं ताकि नशे की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से नकेल कसी जा सके।	पुलिस विभाग
113.	प्रदेश के बर्फीले ईलाकों जैसे लाहौल स्पिती, पांगी, डोडरा के ऊंचे क्षेत्र आदि में सिंचाई तथा पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए डीआरडीओ के साथ मिलकर उनके द्वारा उपयोग की जा रही पाईपों, तकनीक, को अपनाकर, परीक्षण कर उपरोक्त स्थानों पर उसी तकनीक और पाईपों (बर्फ में न जमने वाली) का इस्तेमाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
114.	लाहौल स्पिति के काजा में आईसीएमआर की टीम को भेजा जाए और वहां के लोगों में अलसर, कैंसर, हेपाटाईटिस–बी के बढ़ते मामलों की जांच की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
115.	लाहौल स्पिति में केलांग के ऊपर मांचु के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन/पर्वतारोहण खेल संस्थान
116.	लाहौल स्पिति क्षेत्र की जनता को बिजली की समस्या से स्थायी निजात दिलाने के लिए 4 मेगावॉट के प्रोजेक्ट कार्य को सितम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाए और अक्तूबर से बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही इसमें 1 मेगावॉट का बैटरी बैकअप भी रखा जाए।	HPPCLtd./ हिम ऊर्जा विभाग
117.	स्पिति से मुदभावा होकर रामपुर के लिए पिनवैली में सुरंग के साथ सड़क निर्माण की डीपीआर/प्रस्तावना (वाईब्रेंट विलेज सड़क के नाम से) बनाकर केन्द्र से स्वीकृत करवाई जाए। साथ ही इसके एफसीए तथा एफआरए के मामलों को उपायुक्त किन्नौर तथा लाहौल मिलकर शीघ्र निपटान करे।	लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त किन्नौर तथा लाहौल स्पिति

(अनुबन्ध 'क')

वार्षिक योजना बजट (2023–24) के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 01, 02 तथा 03 फरवरी, 2023 को होने वाली बैठकों के लिए माननीय मुख्य मन्त्री, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु का उद्घाटन भाषण।

---

1. मैं, समस्त प्रतिभागियों का वार्षिक योजना वर्ष 2023–24 के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा हेतु आयोजित इस बैठक में स्वागत करता हूँ।
2. इस बैठक में होने वाले विचार विमर्श तथा परामर्श से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। हम प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों के त्वरित व सन्तुलित विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। मैं आपकों सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज मानकर इसके प्रभावी कार्यन्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
3. हमारा प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन प्रदान किया जाए। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे।
4. हमारी सरकार ने वार्षिक योजना 2023–24 के आकार को रू0 9523.82 (नौ हजार पांच सौ तेईस दशमलव बयासी) करोड़ प्रस्तावित किया है।
5. वर्ष 2022–23 के दौरान नाबार्ड से रू0 809.43 करोड़ (आठ सौ नौ दशमलव तेतालीस करोड़) की जिसमें लोक निर्माण विभाग की 81 (ईक्यासी) एवं जल शक्ति विभाग की 69 (उन्हत्तर) विधायक प्राथमिकताएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।
6. माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सामान्यतः नाबार्ड संचालित **RIDF** कार्यक्रम से **Finance** किया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सर्वप्रथम केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित करने का प्रयास किया जाता है।
7. आप सभी प्रदेश की प्रमुख समस्याओं से भली भान्ति परिचित हैं। आवश्यकता है कि हम इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए संतुलित योजनाएं तैयार करें तथा इनके कार्यन्वयन को गति प्रदान करें। मैं, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी विकास कार्यक्रमों के संचालन में सरकार को सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे।
8. वर्ष 2023–24 के लिए सड़क एवं पुल, लघु सिंचाई, ग्रामीण पेयजल योजना एवं मल निकासी विकास शीर्षों में प्रति विधायक वास्तविक नई 06 योजनाएं बजट में सम्मिलित करने का प्रावधान है। माननीय विधायकों को यह छूट होगी कि वे सभी 06 योजनाएं किसी एक ही विकास शीर्ष अथवा दो विकास शीर्षों या तीनों विकास शीर्षों में प्रस्तावित कर सकते हैं।

9. पहली बार चुनकर आए विधायकों से अनुरोध है कि वह अपनी विकास योजनाओं की सूचना यदि निर्धारित प्रपत्र पर इस बैठक में उपलब्ध न करवा सकें तो अतिशीघ्र योजना विभाग को अलग से भिजवा दें ताकि उन्हें आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जा सके। मेरा समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से भी अनुरोध है कि वे माननीय विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं / शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न बरतें तथा उनके बहुमूल्य सुझावों पर अमल करें। विशेषतः लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग से आग्रह रहेगा कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 962 (नौ सौ बासठ) करोड़ के बजट परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति (**reimbursement**) दावे दिनांक 15 मार्च, 2023 से पहले जमा करें।

10. माननीय विधायकों द्वारा दी गई योजनाओं की डी.पी.आर. के बनने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए **FCA/FRA/Gift deed** आदि औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से निराकरण के लिए मैं निर्देश देता हूँ कि सम्बन्धित विभाग और उपायुक्त भी अपने स्तर पर हर महीने प्राथमिकताओं की समीक्षा करेंगे जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए।

11. दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि करने तथा इस क्षेत्र में अतिरिक्त स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार इस दिशा में कई कारगर कदम उठाने जा रही है।

12. आपको प्रेषित प्राथमिकताओं के प्रपत्र–I के साथ हमने प्रपत्र–II भी संलग्न किया है जिसमें प्रदेश की विकास नीति, वित्तीय संसाधन जुटाने, मितव्ययता, बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व रोजगार सृजन इत्यादि महत्वपूर्ण मुददों पर सुझाव मांगे गए हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन विषयों पर भी अपने बहुमूल्य सुझाव बैठक में रखें।

13. मैं, इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करता हूँ कि बारी–बारी से सभी माननीय विधायक अपने बहुमूल्य विचार इस बैठक में रखें।

***

मानननीय विधायकों के साथ निर्धारित बैठकों की संशोधित जिलावार समय सारणी

क्र. सं.	जिले का नाम (निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या)	दिनांक	समय
1.	1. ऊना (5) 2. हमीरपुर (5) 3. कुल्लू (4) 4. सिरमौर (5)	01-02-2023	अपराहन् 2:00 से 5:00 बजे
2.	1. कांगड़ा (15) 2. किन्नौर (1)	02-02-2023	पूर्वाहन् 10:30 से 1:30 बजे
3.	1. सोलन (5) 2. बिलासपुर (4) 3. मण्डी (10)	02-02-2023	अपराहन् 2:00 से 5:00 बजे
4.	1. चम्बा (5) 2. शिमला (8) 3. लाहौल व स्पीति (1)	03-02-2023	पूर्वाहन् 10:30 से 1:30 बजे

***

माननीय मुख्य मन्त्री, हि0प्र0, की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की तीन दिवसीय बैठकों में जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार भाग लेने वाले माननीय मन्त्री एवं माननीय विधायकों का ब्यौरा ।

क्र. सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पदनाम
1.	2.	3.	4.	5.
01–02–2023 (सांयः 2:00 बजे से 5:00 बजे तक)				
1.	ऊना	1. गगरेट	श्री चैतन्य शर्मा	माननीय विधायक
		2. हरोली	श्री मुकेश अग्निहोत्री	माननीय उप मुख्यमंत्री
		3. ऊना	श्री सतपाल सिंह सत्ती	माननीय विधायक
		4. कुटलैहड़	श्री दविन्द्र कुमार (भुटटो)	माननीय विधायक
2.	हमीरपुर	1. भोरंज	श्री सुरेश कुमार	माननीय विधायक
		2. सुजानपुर	श्री राजिन्द्र राणा	माननीय विधायक
		3. हमीरपुर	श्री आशीष शर्मा	माननीय विधायक
		4. बड़सर	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	माननीय विधायक
		5. नदौन	श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खू	माननीय मुख्य मन्त्री
3.	कुल्लू	1. मनाली	श्री भुवनेश्वर गौड़	माननीय विधायक
		2. कुल्लू	श्री सुन्दर सिंह ठाकुर	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		3. बन्जार	श्री सुरेन्द्र शौरी	माननीय विधायक
		4. आनी	श्री लोकेन्द्र कुमार	माननीय विधायक
4.	सिरमौर	1. पच्छाद	श्रीमति रीना कश्यप	माननीय विधायिका
		2. नाहन	श्री अजय सोलंकी	माननीय विधायक
		3. श्री रेणुका जी	श्री विनय कुमार	माननीय विधायक
		4. पांवटा	श्री सुख राम चौधरी	माननीय विधायक
		5. शिलाई	श्री हर्षवर्धन चौहान	माननीय मंत्री (उद्योग)
02–02–2023 (प्रातः 10:00 बजे से 1:30 बजे तक)				
5.	कांगड़ा	1. नूरपुर	श्री रणबीर सिंह	माननीय विधायक
		2. इन्दौरा	श्री मलेन्द्र राजन	माननीय विधायक
		3. फतेहपुर	श्री भवानी सिंह पठानिया	माननीय विधायक
		4. ज्वाली	श्री चन्द्र कुमार	माननीय मंत्री (कृषि)
		5. जसवां–प्रागपुर	श्री बिक्रम सिंह	माननीय विधायक
		6. ज्वालामुखी	श्री संजय रतन	माननीय विधायक
		7. जयसिंहपुर	श्री यादविन्द्र गोमा	माननीय विधायक
		8. सुलह	श्री विपिन सिंह परमार	माननीय विधायक
		9. नगरोटा	श्री रघुवीर सिंह बाली	माननीय अध्यक्ष(पर्यटन निगम)
		10. कांगड़ा	श्री पवन कुमार काजल	माननीय विधायक
		11. शाहपुर	श्री केवल सिंह	माननीय विधायक
		12. धर्मशाला	श्री सुधीर शर्मा	माननीय विधायक
		13. पालमपुर	श्री आशीष बुटेल	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		14. बैजनाथ	श्री किशोरी लाल	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
6.	किन्नौर	1. किन्नौर	श्री जगत सिंह नेगी	माननीय मंत्री (राजस्व)

02–02–2023 (सांयः 2:00 बजे से 5:00 बजे तक)				
7.	सोलन	1. अर्की	श्री संजय अवस्थी	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		2. नालागढ़	श्री के.एल. ठाकुर	माननीय विधायक
		3. दून	श्री राम कुमार	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		4. सोलन	डॉ0 धनी राम शॉंडिल	माननीय मंत्री (स्वास्थ्य)
		5. कसौली	श्री विनोद सुल्तानपुरी	माननीय विधायक
8.	बिलासपुर	1. झण्डूता	श्री जीत राम कटवाल	माननीय विधायक
		2. घुमारवीं	श्री राजेश धर्माणी	माननीय विधायक
		3. बिलासपुर	श्री सुभाष ठाकुर	माननीय विधायक
		4. श्री नैना देवी जी	श्री रणधीर शर्मा	माननीय विधायक
9.	मण्डी	1. करसोग	श्री दीप राज	माननीय विधायक
		2. सुन्दर नगर	श्री राकेश कुमार	माननीय विधायक
		3. नाचन	श्री विनोद कुमार	माननीय विधायक
		4. द्रंग	श्री पूर्ण चन्द ठाकुर	माननीय विधायक
		5. जोगिन्द्रनगर	श्री प्रकाश राणा	माननीय विधायक
		6. धर्मपुर	श्री चन्द्र शेखर	माननीय विधायक
		7. मण्डी	श्री अनिल शर्मा	माननीय विधायक
		8. बल्ह	श्री इन्द्र सिंह	माननीय विधायक
		9. सरकाघाट	श्री दलीप ठाकुर	माननीय विधायक
03–02–2023 (प्रातः 10:00 बजे से 1:30 बजे तक)				
10.	चम्बा	1. चुराह	श्री हंस राज	माननीय विधायक
		2. भरमौर	डॉ0 जनक राज	माननीय विधायक
		3. चम्बा	श्री नीरज नैययर	माननीय विधायक
		4. डलहौजी	श्री डी.एस. ठाकुर	माननीय विधायक
		5. भटियात	श्री कुलदीप सिंह पठानिया	माननीय अध्यक्ष(हि0प्र0वि0स0)
11.	शिमला	1. चौपाल	श्री बलबीर सिंह वर्मा	माननीय विधायक
		2. ठियोग	श्री कुलदीप राठौर	माननीय विधायक
		3. कसुम्पटी	श्री अनिरुद्ध सिंह	माननीय मंत्री (पंचायती राज)
		4. शिमला–शहरी	श्री हरीश जनारथा	माननीय विधायक
		5. शिमला–ग्रामीण	श्री विक्रमादित्य सिंह	माननीय मंत्री(लोक निर्माण)
		6. जुब्बल–कोटखाई	श्री रोहित ठाकुर	माननीय मंत्री (शिक्षा)
		7. रामपुर	श्री नन्द लाल	माननीय विधायक
		8. रोहड़ू	श्री मोहन लाल बराकटा	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
12.	लाहौल–स्पीति	1. लाहौल–स्पीति	श्री रवि ठाकुर	माननीय विधायक

***